टिप्पणी

30

स्थानीय क्षेत्र नियोजन

स्थानीय स्तर की समस्याओं और मुद्दों के समाधान से सम्बंधित योजना बनाने की प्रक्रिया 'स्थानीय क्षेत्र नियोजन' कहलाती है। लोगों का पूरा कल्याण करना और स्थानीय क्षेत्र का विकास करना इसकी प्राथमिकताएं हैं। सामाजिक सेवाओं व सुविधाओं को बनाए रखना, स्थानीय उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता व मात्रा में प्रौन्नति और परिवेश तथा स्थानीय पर्यावरण को स्वच्छ और हरित बनाए रखना इसके कुछ सतत् प्रयोजन होते हैं। लोगों और स्थानों से सम्बंधित यह आकार में लघुत्तम नियोजन इकाई है। लोगों की भागीदारी के जरिए जो नियोजन किया जाता है वो स्थानीय क्षेत्र में सतत् वृद्धि तथा विकास प्रतिबिम्बित करने वाली वास्तविक स्थिति बन जाता है। आप स्थानीय क्षेत्र का अर्थ व अवधारणाओं, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाई गई स्थानीय क्षेत्र नियोजन की विभिन्न विचार–पद्धतियों (अभिगमों) और स्थानीय क्षेत्र नियोजन प्रयासों की सफलताओं के बारे में इस पाठ में ज्यादा विस्तार से अध्ययन करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात् आपः

- स्थानीय क्षेत्र नियोजन, विकास के पारिस्थितिक तथा सामाजिक–आर्थिक आधार को समझा सकेंगे;
- 'नियोजन स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का इस्तेमाल करने में कैसे मदद करता है' की ख्याख्या कर सकेंगे;
- विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत स्थानीय क्षेत्र का विकास करने के लिए विकसित हुई भिन्न विचार पद्धतियों और उनके उद्देश्यों की तुलना कर पाएंगे;
- भारत के विभिन्न नियोजन क्षेत्रों और उनकी अनूठी जरूरतों को मानचित्र में पहचान सकेंगे;

टिप्पणी

- नक्शे द्वारा बता सकेंगे कि किस प्रकार पारिस्थितिकी, पर्यावरण और संसाधन उपयोग एक–दूसरे से सम्बंधित है और किस प्रकार स्थानीय क्षेत्र नियोजन के लिए इनका प्रबंध किया जाएगा।

30.1 स्थानीय क्षेत्र नियोजन की अवधारणा

स्थानीय क्षेत्र नियोजन से सम्बंधित अवधारणाओं और विचार पद्धतिओं को समझाने के लिए, हमें उस पूरे विचार को गठित करने वाले शब्दों को समझना होगा। 'स्थानीय क्षेत्र' शब्द का उपयोग पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज में भिन्न–भिन्न तरह से किया जाता है। यह स्थल–विशेष मुद्दा, वस्तु या समुदाय है। विशेषताओं के रूप में, स्थानीय क्षेत्र की भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं दोनों होती हैं जैसे कि भूदृश्य, इलाके का परिवेश, स्थानीय उत्पाद, लोक नृत्य और दस्तकारी, इत्यादि।

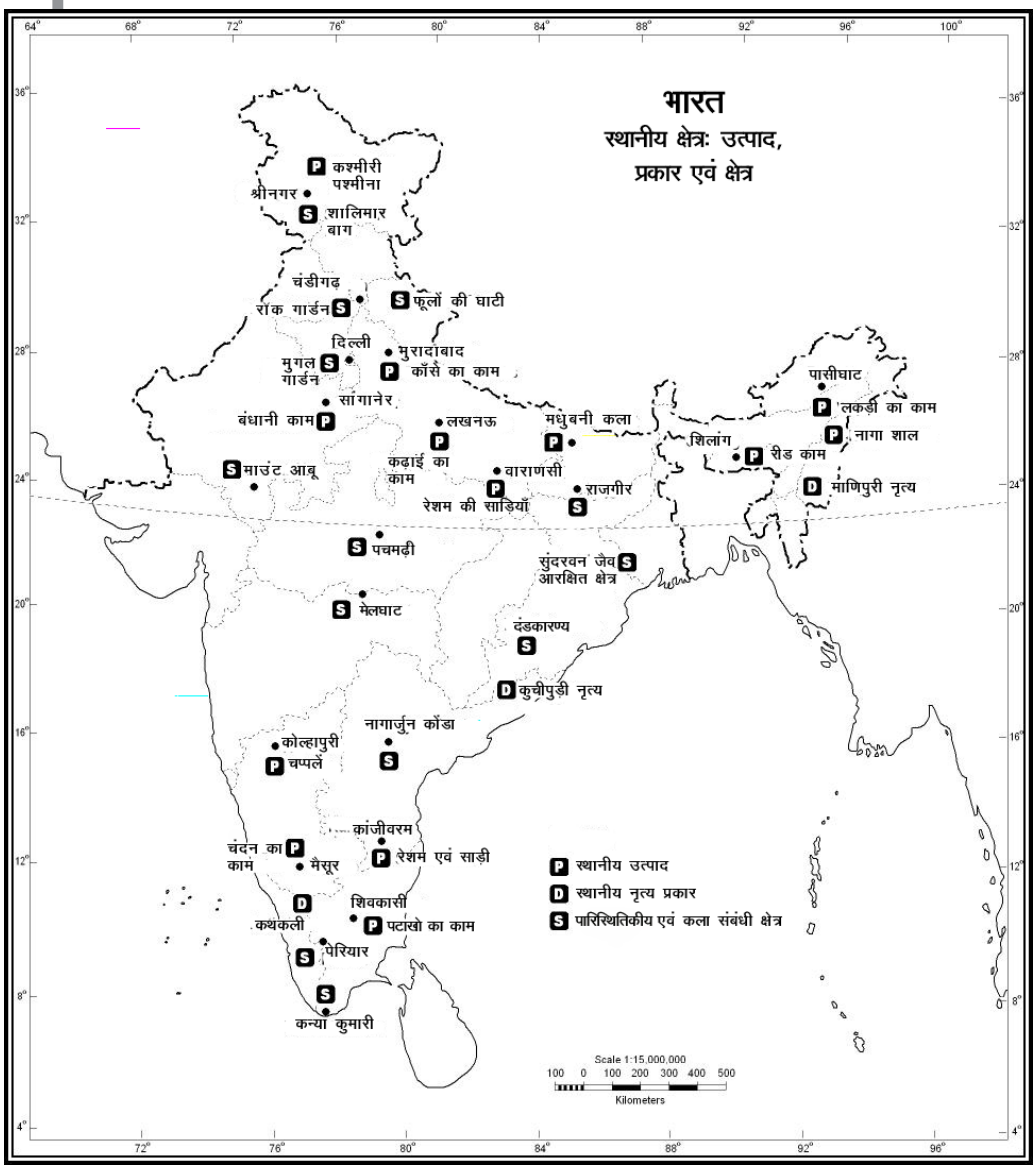

चित्र 30.1 स्थानीय क्षेत्रः उत्पाद, नृत्य एवं स्थल

टिप्पणी

स्थानीय क्षेत्र की विशेषताएँ स्थान/ठिकाने और लोगों के साथ सम्बंध के शक्तिशाली बन्धन को प्रतिबिम्बित करती हैं। गैर स्थानीय क्षेत्र और लोगों के सम्बंध में, यह सम्बंध के निर्बल होते अनुबंध और बढ़ती हुई भिन्नताएं प्रतिबिम्बित करती हैं। उदाहरण के लिए समुद्री समीर, स्थानीय पवन समुद्र के किनारे काफी प्रभाव डालती है और समुद्र से दूर यह निर्बल होती जाती है। कभी–कभी स्थानीय क्षेत्र उत्पाद या पहचान इतनी लोकप्रिय और विशिष्ट बन जाती है कि दूसरे स्थानों व क्षेत्रों में उसकी मांग की जाने लगती है। कोल्हापुर की चप्पल, मैसूर की चंदन की अगरबत्ती, शिवकासी के पटाखे, नागा शालें, कश्मीरी पश्मीना, वाराणासी की रेशमी साड़ियां, मधुबनी कला, कुच्चीपुड़ी नृत्य इत्यादि कुछ स्थानीय क्षेत्र उत्पाद और विशिष्टताएं हैं, जिनकी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत मांग है। अच्छे से बनाकर रखा इलाका अपने स्वच्छ और हरित पर्यावरण के साथ गैर–स्थानीय लोगों के लिए आर्कषण के स्रोत के रूप में कार्य करता है और दूसरे स्थानों को इसे आदर्श रूप में अपनाने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए शालीमार बाग (श्री नगर), मुगल गार्डन (दिल्ली), फूलों की घाटी (उत्तराखंड) रॉकगार्डन (चण्डीगढ़), नागार्जुन कोण्डा (आन्ध्र प्रदेश), राजगीर (बिहार), कन्याकुमारी (तमिलनाडु) इत्यादि स्थानीय क्षेत्र के स्थल हैं जो पारिस्थितिक और सौन्दर्य–बोध विषयक महत्व का अच्छा सन्तुलन पेश करते हैं। स्थानीय उत्पाद, क्षेत्र और लोगों से लगाव और उनके प्रति गर्व का भाव, एकता और गतिविधि का स्रोत होता है। यह सामान्य समझ और पहचान की ओर भी अग्रसर करता है। पारिस्थितिक रूप से, स्थानीय क्षेत्र पर्वतीय, पठारी, मैदानी, समुद्र तटीय, मरुस्थलीय या आर्द भूस्थल हो सकते हैं। प्रकार्यात्मक रूप से, स्थानीय क्षेत्र चारागाही, कृषि प्रधान, औद्योगिक, संस्थानिक या सेवा प्रधान क्षेत्र हो सकते हैं। निवास स्थान के रूप में, स्थानीय क्षेत्र ग्रामीण, शहरी, यायावर या जनजातीय हो सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र अपने सामाजिक व्यवस्था के सम्बध में आधुनिक या पारम्परिक हो सकते हैं। उसी तरह से, आर्थिक विकास के रूप में, स्थानीय क्षेत्र विकसित या कम विकसित हो सकते हैं।

क्षेत्र और उसके लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए तरीके और माध्यमों का उपाय निकालने का प्रयत्न ''नियोजन'' कहलाता है। एक विद्यार्थी के रूप में, हम अध्ययन, परीक्षाओं और अन्य दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए योजना बनाते हैं। हम जहां काम करते हैं और जहां रहते हैं वहां स्थानीय स्तर की सामान्य समस्याओं के हल ढूंढ़ने में भी अपने को जोड़ लेते हैं। सुख–साधन और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, साफ–सफाई, सामान्य स्वास्थ्य और शिक्षा कुछ सर्वाधिक आम समस्याएं हैं जिनका कि स्थानीय लोग सामना करते हैं। स्थानीय क्षेत्र क्योंकि नियोजन की लघुत्तम इकाइयाँ हैं उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढ़ना आसान होता है। उनकी समस्याएं ज्यादा छोटी होती हैं और उनके आयाम का प्रबन्धन आसान होता है। अधिकांश समस्याएं जिनके लिए नियोजन और समाधान की आवश्यकता होती है, वह. पारिस्थितिक असन्तुलन, आर्थिक मन्दी और सामाजिक तनावों से संबधित होती हैं। स्थानीय क्षेत्र में लोगों की सामान्य स्थितियों को सुधारने के लिए मूलभूत सामाजिक सुख–साधन और सुविधाओं की व्यवस्था की योजना बनाने की जरूरत होती है। स्थानीय लोगों की सहभागिता,

टिप्पणी

स्थानीय पदार्थों, देसी ज्ञान का उपयोग करने में, और आधारिक ढ़ांचे, जिसके लिये योजना बनाई है, को बनाए रखने में सहायता करती है। नियोजन का लक्ष्य, वृक्षारोपण, स्थानीय जल भंडार जैसे नदी, तालाब, झील इत्यादि की देखरेख और शैल व मृदा के प्रबन्धन द्वारा, स्थानीय पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने का भी होता है। स्थानीय क्षेत्र के नियोजन में लोगों की सहभागिता और उनके रख–रखाव में सतत सहभागिता के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्यपूर्ण स्थानीय पर्यावरण विकसित होता है।

''अतः नियोजन दिए गए समय में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार स्थानीय लोगों और सरकार द्वारा पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक कार्यकलापों को सोचने, समझने, प्रारंभ करने, नियमित और नियंत्रित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है।''

30.2 नियोजन के स्तर

नियोजन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। एक छोटे स्थानीय क्षेत्र से प्रारम्भ करते हुए इतने बड़े जितना कि विश्व स्तर तक नियोजन मानव उन्नति और क्षेत्रीय विकास, का अंतरंग हिस्सा है। आदि काल से लोग अपने कार्यकलाप, गतिविधियां, आवास स्थान इत्यादि की योजना बनाते रहे हैं। अतः यह समय और क्षेत्र को लेकर सतत् प्रक्रिया है और इसका लक्ष्य लोगों का और वातावरण का कल्याण है। भू–मण्डल स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा समस्त विश्व के लिए नियोजन का प्रयास किया गया और अन्य राष्ट्र, नियोजन योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करते हैं। विभिन्न कार्यक्रम जैसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक कार्यक्रम (U.N.E.P), तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (U.N.D.P.) इत्यादि पर्यावरण, निर्धनता, विकास इत्यादि के भू–मण्डलीय मुद्दों के स्तर पर, राष्ट्र के कल्याण और विकास के लिए राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश के कल्याण और विकास के लिए योजनाएँ बनाई जाती हैं। हमारे देश में, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग इत्यादि; भिन्न पारिस्थितिक अंचलों जैसे पर्वत, मरुस्थल, समुद्र तटीय क्षेत्र इत्यादि और समाज के भिन्न वर्गों जैसे स्त्रियां, बच्चे, जनजातीय समूह, युवा, वृद्ध व्यक्ति, इत्यादि के लिए योजना बनाने का कार्य केन्द्रीय एजेन्सी योजना आयोग करता है। प्रधानमन्त्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। राष्ट्र को प्रशासनिक और नियोजन के उद्देश्यों के लिये आगे कई उप–इकाइयों में विभाजित किया जाता है। यह प्रत्येक राष्ट्र में भिन्न नाम के होते हैं। हमारे देश में, राष्ट्र को राज्यों, जिला और खण्डों में उप–विभाजित किया है। राज्य के स्तर पर राजकीय नियोजन परिषद है जो पूरे राज्य के लिए योजना तैयार करता है। इसे प्रादेशिक योजना के नाम से भी जानते हैं। राज्य का मुख्यमन्त्री राजकीय नियोजन परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्र व राज्यों के बाद तृतीय क्रम की नियोजन इकाईयां जिले हैं। जिले के स्तर पर, नियोजन और विकास संस्थाएं एक साथ कार्य करती हैं और जिलाधीश योजना क्रियान्वयन का समन्वय करता है। सामुदायिक विकास खण्ड चौथे स्तर की लघु नियोजन इकाइयां हैं। प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड के अंतर्गत

टिप्पणी

लगभग 50 गांव होते हैं। ये खण्ड, गांव और परिवार के स्तर पर योजना क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। खंड विकास अधिकारी नियोजन के इस स्तर पर योजना का समन्वयक होता है। स्थानीय क्षेत्र नियोजन छोटे इलाके जैसे गांव, बस्ती या मोहल्ले के लिए होता है। एक स्थान पर निवास कर रहा और काम कर रहा समस्त समुदाय, योजनाओं को बनाने और सरकारी संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों व अन्य से सहायता तथा सहयोग पाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह प्रयास सिर्फ कुछ लोगों का नहीं होता है बल्कि बहुत से व्यक्तियों की मेहनत होती है जो स्थानीय क्षेत्र को स्वच्छ, हरित और समृद्धशाली बनाती है।

नियोजन के भिन्न स्तरों का चित्रीय प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

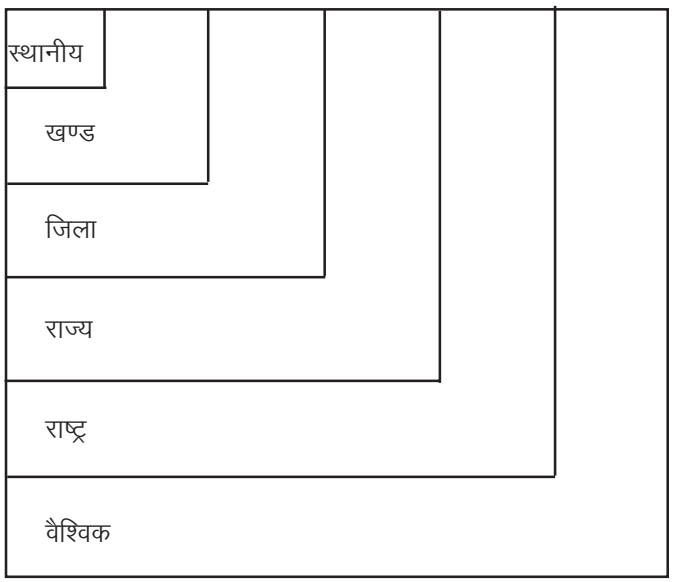

चित्र 30.2 नियोजन के स्तर

तालिका क. 30.1 नियोजन के स्तर

नियोजन का प्रकार	स्तर
वैश्विक नियोजन	I
राष्ट्रीय नियोजन	II
राज्य नियोजन	III
जिला नियोजन	IV
ब्लाक या लघु स्तरीय नियोजन	V
स्थानीय क्षेत्र नियोजन	VI

टिप्पणी

30.3 नियोजन की चुनौतियां

किसी कार्यक्रम के नियोजन की सफलता के लिए गम्भीर चुनौतियां होती है। अक्सर नियोजन शुरू कर दिया जाता है और क्षेत्र व लोगों, जिनके लिये योजना बनाई है, पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में यथोचित विचार नहीं किया जाता है। नियोजन क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तो यह जिन क्षेत्रों और लोगों के लिए बनाया जाता है उन तक पहुँचने से पहले विभिन्न स्तरों पर अवरुद्ध हो जाता है। तुलनात्मक रूप से उच्च आर्थिक विकास के बावजूद भारत सामाजिक प्रगति के मामले में निरन्तर पीछे चल रहा है। हमारे देश में निर्धन, कुपोषित और निरक्षर व्यक्तियों का अधिकतम संकेन्द्रण है। इन गम्भीर चुनौतियों को सरकारी या कुछ गैर–सरकारी एजेन्सी स्तर के जरिए नहीं संचालित किया जा सकता है, इसके लिए स्थानीय लोगों की प्रभावपूर्ण सहभागिता और सहयोग की जरूरत है। लोग चाहते हैं और योजना बनाते हैं कि सड़क उनके घर के दरवाजे तक पहुँचे, प्रत्येक बच्चा स्कूल में पढ़े, उनके पास ऊर्जा और सुरक्षित पेयजल हो, उनके पास खेतों की सिंचाई के लिए जल हो और अपने स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए बाजार हो। अतः स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा आधारिक ढांचा लोगों को जागरूकता, उनकी प्रभावपूर्ण सहभागिता और उनकी सक्रियता सुनिश्चित कर सकता है, जो कि कार्यक्रम के नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक है। यदि नियोजन को सफल करना है और उसे बनाए रखना है तो पारिस्थितिक और आर्थिक पहलुओं में पूर्ण सन्तुलन होना चाहिए।

स्थानीय क्षेत्र नियोजन की मूलभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं :

1. उद्देश्यों या लक्ष्यों को सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करना।
2. नियोजन के लक्ष्य और प्राथमिकताएं जिन्हें प्राप्त करना है को निर्धारित करना।
3. योजना को कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों का संग्रह करना।
4. योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सामाजिक समूह या संगठन सृजित करना।
5. की गई प्रगति का नियमित मूल्यांकन और जांच–पड़ताल करना।

पाठगत प्रश्न 30.1

1. स्थानीय क्षेत्र और नियोजन की परिभाषा दीजिए।

_____

2. भारत में नियोजन के विभिन्न स्तर कौन से हैं?

_____

टिप्पणी

3. किसी क्षेत्र के नियोजन के लिए तीन चुनौतियां बताइए।

_____

4. नियोजन से लोगों की मूलभूत अपेक्षाएं क्या हैं?

_____

5. नियोजन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं?

_____

30.4 नियोजन का आधार

नियोजन के कई आधार हो सकते हैं परन्तु यहां हम नियोजन के सिर्फ पारिस्थितिक और सामाजिक–आर्थिक आधार की चर्चा कर रहे हैं।

(क) नियोजन का पारिस्थितिक आधार

समस्त प्राकृतिक जीवों का उनके वातावरण के साथ अंतर्सम्बन्ध वर्णन करने वाला शास्त्र पारिस्थितिक विज्ञान कहलाता है। वो सब स्थितियां, परिस्थितियां और प्रभाव जो किसी एक जीव या जीवों के समूह के विकास को प्रभावित करती हैं पर्यावरण कहलाती है। अतः पारिस्थतिकी और पर्यावरण, जीवों और व्यवस्थाओं जो उन पर असर डालती है, के सन्दर्भ में, एक दूसरे के साथ घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है। भौगोलिक रूप से, भूमि और समुद्र के बीच पदार्थ का विनिमय दो मुख्य भौतिक–भौगोलिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रारम्भ होता है।

मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतर्क्रिया अपृथकनीय है। यह सामान्य रूप से जीवन और विशेषतया पर्यावरण के बीच अंतर्क्रिया का उच्चतम स्वरूप है। करोड़ों वर्षों से अधिक समय में विकसित हुए जीवन के रूपों की विविधता और उनकी भिन्न, अक्सर विषम पर्यावरण सम्बन्धी स्थितियों से सामंजस्य आश्चर्यजनक है। मनुष्य का प्रकृति के साथ सामंजस्य उस समय प्रारम्भ हुआ जब उसने अपने को प्राकृतिक पर्यावरण से पृथक कर लिया था। मनुष्य और प्रकृति के बीच सम्बन्ध उसके आवास के भीतर गढ़े जाते हैं।

मनुष्य–प्रकृति अंतर्क्रिया का अनुभव नियोजन की सदियों पुरानी परिपाटी है। प्रकृति का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, मनुष्य पारिस्थितिक व्यवस्था में आवश्यक समायोजन करता आ रहा है। पारिस्थितिक व्यवस्था को संतुलन में रखते हुए, लोगों के कल्याण के लिए नियोजन के कुछ उदाहरण हैं—जंगली पशुओं को पालतू बनाना, प्राकृतिक वनस्पति से लाभकारी पौधों को चुनना, पर्वतीय ढलानों को सीढ़ीदार बनाना, सिंचाई के लिए नदियों को वश में करना या बाढ़ नियंत्रण इत्यादि। मानवीय निवास स्थान जल स्रोतों के, कार्यस्थलों के बहुत निकट सान्निध्य में और सुरक्षा तथा गतिशीलता को

टिप्पणी

विचार में रखते हुए योजनाबद्ध किए गए थे। अधिकांश प्राथमिक धन्धे जैसे कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन इत्यादि उत्पादकता के स्वाभाविक विचार पर आधारित हैं। इसी तरह से, कुछ गौण उत्पादन तन्त्र जैसे सॉफ्टवेयर, कागज, कई स्वच्छंद उद्योग इत्यादि की रूपरेखा भी इस तरह से बनाई गई कि वो पारिस्थितिक व्यवस्था में न्यूनतम बाधा उत्पन्न करे। तथापि, मानव की बढ़ती हुई जरुरतों और वाणिज्य का ध्यान रखने से पारिस्थितिक व्यवस्था को गम्भीर क्षति पहुँची है। बड़े पैमाने पर विकासात्मक गतिविधियां, वनोन्मूलन, संरचनात्मक परिवर्तन, अवशेष सृजन, आदि ने रिक्तीकरण, भू–मण्डलीय उष्मा, हिमक्षेत्रों का पिघलना, समुद्री स्तर में बढ़ोत्तरी, प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि की गति तेज कर दी है।

(ख) नियोजन का सामाजिक-आर्थिक आधार

पृथ्वी की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और 6 अरब के बिन्दु से ऊपर हो गई है। लोगों की हमेशा बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा। इसलिए, एक निश्चित पारिस्थितिक व्यवस्था में संसाधन उपयोग के दायरे और मानव की जरूरतों के बीच साम्य बनाए रखना आवश्यक है। सतत् पोषणीय विकास के लिए सामाजिक–आर्थिक नियोजन को पारिमित्र बनाए रखना है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के अलावा, स्थानीय परिवेश, गलियों, नालियों, पार्क, खेल के मैदान, खुली जगह इत्यादि को भू–दृश्यों और वृक्षारोपण के साथ विकसित करने के दीर्घीकृत प्रयत्न करने की जरूरत है। वृक्षारोपण की रूपरेखा; भू–विज्ञान सम्बन्धी ढांचे, भू–आकृति, जलवायु सम्बन्धी स्थितियां, मृदा, जल निकास प्रणाली और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर बनानी चाहिए। बौने, मध्यम और बड़े वृक्षों की देशी किस्मों का रोपण उपलब्ध जगह, पौधों की स्थितियों, स्थानीय मौसम और जलवायु सम्बन्धी स्थितियों के आधार पर करना चाहिए। स्थानीय पर्यावरण को प्रौन्नत और बनाए रखने के लिए, लोगों की मदद अनिवार्य है। बदले में स्वास्थ्यपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकीय व्यवस्था स्थानीय लोगों की बहुत सी जरूरतों को पूरा करती है और साथ ही हरित परिवेश का सुखद दृश्य प्रस्तुत करती है।

30.5 स्थानीय क्षेत्र नियोजन के आयाम

(क) मूलभूत और उच्चतर आवश्यकताएँ

''स्थानीय'' समुदाय का कल्याण लोगों की मूलभूत और साथ ही उच्चतर आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर करता है। मूलभूत आवश्यकताओं में सुरक्षित पेय जल, बेसिक शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और संचार सुविधाओं इत्यादि के अलावा खाद्य पदार्थ, कपड़ा और मकान शामिल हैं। उच्चतर जरूरतों में अभी और ज्यादा उच्च क्रम के सुख–साधन, सेवाएं और सुविधाएं इत्यादि शामिल हैं। उच्चतर जरूरतें समाज को कुशल, सेवा–अभिमुख और गतिशील बनने में मदद करती हैं। जबकि मूलभूत जरूरतें जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, नियोजन की प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों और स्थानों की मांगों को पूरा करना है। नियोजन की कई योजनाओं को लोगों की सामान्य और

टिप्पणी

साथ ही प्रकार्यात्मक जरुरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तथापि, जनसंख्या वृद्धि और गतिविधियों का विशिष्ट स्थलों पर केन्द्रीयकरण नियोजन प्रक्रिया के लिए चुनौती पेश करता है।

(ख) जनसंख्या वृद्धि और भावी नियोजन

जिन स्थानों पर जनसंख्या वृद्धि सामान्य रहती हैं, वहां प्रकार्यात्मक गतिविधियां सामान्यतः अपरिवर्तित रहती हैं और नियोजन की योजना सफल हो जाती है। उदाहरण के लिए, सिविल लाइन्स, माल रोड, छावनी बस्तियां इत्यादि स्थानीय जनसंख्या की वृद्धि के साथ सुख–साधनों और सुविधाओं के समान और प्रकार्यों तथा गतिविधियों के केन्द्रीयकरण के बीच असाधारण सन्तुलन पेश करते हैं। इसके विपरीत, उन स्थानीय क्षेत्रों में, जहां जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा है और गतिविधियों का केन्द्रीयकरण अबाधित जारी रहता है, नियोजन का सम्पादन सामान्यतः बुरा रहता है। उदाहरणार्थ, व्यस्त बाजार, औद्योगिक स्थल, परिवहन जंक्शन, झुग्गी–झोपड़ी की बस्तियां इत्यादि तुलनात्मक रूप से जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि और गतिविधियों का ज्यादा केन्द्रीयकरण प्रकट करते हैं। यह संकुलन और भीड़–भाड़ को बढ़ावा देता है जो कि नियोजन की असफलता को प्रतिबिम्बित करता है।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार अवसरों की अनुपस्थिति में, अधिकांश ग्रामीण युवा शहरों की ओर जाने लगते हैं। यह मूल स्थानों में आर्थिक स्थिति को और कमजोर और गंतव्य स्थानों में जनसंख्या के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा देता है। प्रवासी जनसंख्या की सीमित देय क्षमता के कारण ये समूह में इकट्ठे रहते हैं, परन्तु शहरों में ये पर्याप्त सस्ता श्रम उपलब्ध कराते हैं। जनसंख्या वृद्धि और सेवाओं, सुविधाओं और सुख–साधनों के बीच असंतुलन से गंदगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य में कमी और सबसे अधिक, स्थानीय पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः, नियोजन की व्यवस्था इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई स्थानीय मांगों को पूरा नहीं कर पाती।

(ग) स्थायित्व और विकास के लिए आर्थिक आधार

किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास स्थानीय क्षेत्र नियोजन का दूसरा आयाम है। इसका लक्ष्य उत्पादन व सेवाओं के स्तर को बढ़ाना, रोजगार सृजन, संशोधित बाजार तंत्र, अनुकूल मूल्य/कीमत नीति, परिवहन और सम्प्रेषण की दक्ष प्रणालियां, इत्यादि हैं। आर्थिक रूप से, उन्नत क्षेत्र सामान्यतः प्राकृतिक संरक्षण और पारिस्थितिक सुधारों में काफी विनियोग करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह, यदि क्षेत्रों का आर्थिक आधार अच्छा है तो सामाजिक आधारिक ढांचा और सुविधाएं भी सृजित की जा सकती हैं।

लगभग सभी क्षेत्र–ग्रामीण और शहरी, प्राकृतिक सामर्थ्य/अंतःशक्ति से सम्पन्न होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक गतिविधियां प्रमुख स्थान रखती हैं जबकि गौण और सेवा–प्रधान गतिविधियां शहरी क्षेत्रों में प्रमुख होती हैं। आर्थिक वृद्धि की गति प्रौद्योगिकीय विकास और संस्थागत तन्त्र के द्वारा तेज हो जाती है। कृषि का यांत्रिकीकरण और

टिप्पणी

उद्योगों का आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकीय विकास के उदाहरण हैं, जबकि वित्तीय, शैक्षणिक और नीति सम्बन्धी सहायता, क्षेत्र का आर्थिक आधार सुधारने के लिए संस्थागत भूमिकाएँ हैं। उत्पादकों, उपभोक्ताओं, सेवा प्रदान कर्ताओं और कर्मचारियों के हितों जैसे मुद्दों का, नियोजन में ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक पैकेज के स्वाभाविक परिणास्वरूप रोजगान सृजन और आय का दर्जा, बचत और विनियोग की क्षमताएं बढ़ेंगी। यह देखने में आया है कि बहुत से आर्थिक पैकेज समय के साथ लाभकारी बन जाते हैं। शिलांग का सरकण्डे का कार्य (Reed works), मोरादाबद के पीतल के बर्तन, वाराणसी और कांजीवरम का रेशम व ज़री का काम, और सांगानेर का बंधनी का काम, लखनऊ का कढ़ाई का काम इत्यादि सफल कहानियों के कुछ उदाहरण हैं जिनको आर्थिक नियोजन की सहायता मिल गई थी। अतः, स्थानीय क्षेत्र के उत्पाद और सेवाएं उस स्थान की पहचान और लोगों की आर्थिक समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं।

(घ) नियोजन में लोगों की सहभागिता

लोगों की जागरूकता और स्थानीय क्षेत्र नियोजन में उनकी सहभागिता समुदाय के हितों की सुरक्षा कर सकती हैं और साथ ही स्थानीय पारिस्थितिकीय सन्तुलन भी बनाए रखती हैं। जिस नियोजन योजना में स्थानीय लोग जुड़े होते हैं, उसकी असफलता के अवसर न्यूनतम होते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार, शोषण और कु–प्रबन्ध काफी समय तक रूक जाता है। इसके अलावा, उपरोक्त लोग क्योंकि सीधे लाभार्थी होते है, तो वो क्षेत्रीय विकास और सामाजिक कल्याण बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार रवैया रखते हैं। जब स्थानीय लोग योजना तैयार करते हैं और अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं तो यह लोगों के लाभ को अधिकतम और नियोजन की लागत को न्यूनतम रखते हैं। यह ज्यादा सम्भव है कि नियोजन विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि के चक्र और विविधताओं को बढ़ाएगा।

पाठगत प्रश्न 30.2

1. पारिस्थितिकी अनुकूल नियोजन के दो उदाहरण दीजिए।

   (क) _____ (ख) _____

2. संसाधनों और मानवीय आवश्यकताओं के बीच सन्तुलन बनाए रखने की क्या आवश्यकता है?

   _____

3. स्थानीय क्षेत्र में वृक्षारोपण की रूपरेखा बनाने के लिए क्या आधार अपनाना चाहिए?

   _____

टिप्पणी

4. मूलभूत और उच्चत्तर आवश्यकताओं के दो–दो उदाहरण दें

   क) i. _____ ii. _____

   ख) i. _____ ii. _____

5. प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और संस्थागत सहायता, प्रत्येक के दो प्रभाव बताइए।

   क) i. _____ ii. _____

   ख) i. _____ ii. _____

30.6 स्थानीय संसाधनों का आवश्यकता-आधारित उपयोग

स्थानीय लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग किया जाता है। वायु, जल, खाद्य पदार्थ, कपड़ा और मकान मनुष्य के जीवित रहने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। प्रकृति के जैविक और अ–जैविक पदार्थ स्थानीय लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उपयोगी पौधों, पशुओं और प्राकृतिक स्थलों के चयन से मानवीय अनुक्रियाओं जैसे कि खेती, मछली पालन, बागवानी और यायावर पशुपालन। स्थानीय आवश्यकताएं जैसे– भवन निर्माण, गलियों, नालियों, जल स्रोतों, सुन्दर भूदृश्य इत्यादि की स्थानीय संसाधनों द्वारा पूर्ति होती है। क्योंकि अधिकांश पदार्थ स्थानीय लोगों की सामूहिक सम्पत्ति होते हैं, वो सभी के द्वारा निर्माण सामग्री और जीवनयापन के साधनों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः स्थानीय संसाधनों का आवश्यकता आधारित उपयोग उन्हें पारिस्थितिक अनुकूल और आर्थिक रूप से धारणीय बनाए रखता है। स्थानीय संसाधनों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है :

(क) भूमि संसाधन : चट्टानें और मृदाएं:

स्थानीय क्षेत्र की सर्वाधिक असा धारण विशेषता उसकी चट्टानें और मृदाएं हैं। यह भूमि संसाधन सुरम्य भू–दृश्य का आधार होने के अलावा मानवीय आवास और प्राथमिक गतिविधियों का आधार हैं। चट्टानों की अनावृत सतह प्राकृतिक मंचों का कार्य करती है जबकि उसकी ढलानें और सोपान पौधों की वृद्धि का आधार बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में स्थानों को पिकनिक, उद्यान और प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलों के रूप में विकसित किया गया है।

मृदा मानव की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि कृषि, पशुपालन और बागवानी इत्यादि के लिए आधार है। उपजाऊ मृदा मानव सभ्यता और विकास के लिए हमेशा से आकर्षण का स्रोत रही है। तथापि, प्रकृति का यह दुर्लभ उपहार अधिक मृदा अपरदन और निम्नीकरण द्वारा जोखिम में पड़ गया है, और तेजी से बंजर भूमि में बदल रहा है। बड़े पैमाने पर वननाशन और भूमि के वाणिज्यिक उपयोगों ने मृदा के ढांचे में असन्तुलन उत्पन्न कर दिया है। क्योंकि मृदा के निर्माण, उसकी नवीकरण योग्यता और पुनःस्थापन को काफी लम्बा समय चाहिए, इसलिए मृदा

टिप्पणी

संरक्षण और उसकी प्राकृतिक उर्वरा शक्ति बनाए रखने की अत्यन्त आवश्यकता है।

(ख) जल संसाधन

जीवन को दीर्घकालीन आधार पर विकसित करने और बल प्रदान करने के लिए एक सर्वाधिक मूलभूत आवश्यकता जल की उपलब्धता है। यह सभी पारिस्थितिक तंत्रों का केन्द्र है। अधिकांश प्रारंभिक मानव सभ्यताएं जल संसाधनों, विशेष रूप से उपजाऊ नदी घाटियों के समीप विकसित हुई हैं। मानवीय अनुक्रियाओं सभ्यताओं और बस्तियों दोनों के लिए जल अनिवार्य तत्व है। जल को विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों जैसे विद्युत उत्पादन, सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और स्थानीय क्षेत्र को भी स्वच्छ व हरित रखा जाता है।

जल के दुरुपयोग ने जल की कमी उत्पन्न कर दी हैं। जल प्रदूषण से बीमारियाँ हो जाती हैं। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में सूखा और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए, जल का प्रबन्ध जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। जल संग्रहण, जल के अपव्यय को कम करने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए समन्वित प्रयत्न करने की जरूरत है। बरसाती जल के सतही बहाव को रोकने के लिए, जल का, मृदा के अंतः धरातलीय परत तक पुनर्भरण अनिवार्य है। जल के पुनर्भरण में, टैंकों, झीलों, रिसाव गड्ढों, ढलाऊँ सतह के साथ छोटे बांधों का उपयोग मदद करता है।

(ग) बागान/वन संसाधन

पौधे जीवन का मूलभूत आधार हैं और ये ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। वे जीवन निर्वाह और प्राकृतिक आकर्षण का साधन है। जनसंख्या के निरन्तर बढ़ते दबाव के कारण, वन आवरण तेजी से क्षीण हो रहा है जिससे गम्भीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है। राजमार्ग, रेलपथ, पहाड़ी ढलानों, नहरों के बगल में वृक्षारोपण ने सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी इत्यादि जैसी योजनाएँ विकसित की है।

स्थानीय लोगों के संगठित प्रयत्न बागानों और उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह लोगों के रीति–रिवाजों और प्रथाओं के रूप में चला आ रहा है। उदाहरण के लिए, विशेष रूप से हरियाणा और राजस्थान के भागों में विश्नोई समुदाय पौधों की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है, इसी तरह से मैयती विवाह सम्बन्धी रिवाज है जो कुमाऊँ पहाड़ियों में प्रचलित है। वैवाहिक समारोह के दौरान दुल्हन नए पौधे का रोपण करती है और दूल्हा उस पर पानी डालता है। इस रिवाज ने कुमाऊँ में बहुत से गांवों को हरित बना दिया है। वृक्ष आवरण की सुरक्षा, उनका संवर्धन जीवन के भरण–पोषण की बुनियाद है। क्योंकि वृक्ष भवन सामिग्री, ईंधन और विभिन्न प्रकार के फल, फूल और हरित आवरण प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर पर, वृक्ष आवरण की सुरक्षा और बढ़ोतरी जीवन का भरण–पोषण करने के मूल आधार है।

टिप्पणी

30.7 स्थानीय संसाधनों का मूल्यांकन

स्थानीय संसाधनों का मूल्यांकन नियोजन के लिए अनिवार्य है। स्थानीय समस्याओं के हल खोजने और साथ ही विकास के उद्देश्य के लिए हमें स्थानीय संसाधनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सामान्यतः भूमि, मृदा, जल, वन, पशु, अन्य जीव, खनिज इत्यादि किसी एक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इसी तरह से, मानव, उनका शैक्षणिक स्तर, मानवीय अनुक्रियाएँ, कौशल, स्वास्थ्य दर्जा, इत्यादि मानवीय संसाधनों में आते हैं। क्षेत्रीय सर्वेक्षण करके और क्षेत्र के रिकार्ड की मदद से उस स्थान पर उपलब्ध संसाधनों की सूची बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, स्थानीय भूमि संसाधनों के लिए कुल क्षेत्र (गांव के या शहरी इलाके) का अनुमान, चट्टानों और मृदाओं की प्रकृति, भूमि जोतों (कृषि भूमि) का आकार, खण्डों की संख्या, भूमि उपयोग का स्वरूप व प्रकार, इत्यादि के बारे में तथ्य लिखने चाहिए। इसी तरह से, जल संसाधनों के सम्बन्ध में नदी, नाले, तालाब, झील का सर्वेक्षण, उनकी अनुमानित लम्बाई, चौड़ाई और जल की गहराई की जानकारी होनी चाहिए जिससे जल उपलब्धता, जल अतिरेक या कमी की स्थितियों का जल उपभोग से जुड़ी मुख्य समस्याओं का पूर्वानुमान हो सके। वृक्षों, मौसमी पौधों का ईंधन, इमारती लकड़ी, फल और फूलों के रूप में समुदाय के लिए उनके विशिष्ट उपयोग का अनुमान लगाना चाहिए। इसी तरह से, मानवीय और साथ ही पशु संसाधनों का भी मूल्यांकन होना चाहिए।

(क) स्थानीय संसाधनों के मूल्यांकन के लिए आंकड़े एकत्र करने के स्रोत

अतः स्थानीय संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए, हम सरकारी तथा गैर–सरकारी स्त्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। द्वितीयक स्त्रोतों के जरिए जानकारी इकट्ठा करने के अलावा, हम कुछ जानकारी जो कि द्वितीयक स्त्रोतों से उपलब्ध नहीं है अथवा प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण भी कर सकते हैं।

(ख) योजना तैयार करना और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

स्थानीय संसाधनों के मूल्यांकन के आधार पर हमें उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करना चाहिए। इसमें मोटे तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, थोक बाजारों इत्यादि के पहलुओं को शामिल करना चाहिए। योजना को सामुदायिक प्रकार्यों के अलावा, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों की संवृद्धि को भी शामिल करना चाहिए। योजना का संरूपण स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता, लोगों की आवश्यकताओं, सम्भावित व्यय और लोगों को अनुमानित लाभ पर आधारित होना चाहिए। योजना को समय और लक्ष्यों के अनुसार क्रमबद्ध रूप से समाप्त कर देना चाहिए।

स्थानीय क्षेत्रीय योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, स्थानीय लोगों के समर्थन को, श्रम, कच्चे माल, कौशल और मार्गदर्शन के रूप में जुटाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों, स्व सहायता समूहों इत्यादि के समर्थन को वित्त, प्रौद्योगिकी और सामग्री की सहायता के रूप में प्राप्त करना चाहिए। जो काम कर

टिप्पणी

लिया गया हो, उसकी मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण जांच और नियंत्रण प्रयोग में लाना चाहिए।

यह अक्सर देखा जाता है कि इमारतों, नलों का पानी, सार्वजनिक शौचालयों इत्यादि सेवाओं के दुरुपयोग और देखभाल के अभाव में वह ढांचा, जो नियोजन द्वारा एक बार सृजित कर दिया गया, उसका रख–रखाव खराब बना रहता है। स्थानीय संसाधनों को गैर–स्थानीय लोगों द्वारा व्यापारिक उपयोग के लिए खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे संसाधनों के अत्यधिक दोहन और उसके अंततः समाप्त हो जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती हैं। अतः, यह स्थानीय लोगों के लिए आवश्यक है कि वो नियोजित परियोजनाओं के रख–रखाव और देखभाल के बारे में विशेष ध्यान रखें।

अतः यह सिद्ध हो चुका है कि स्थानीय संसाधनों का आवश्यकता–आधारित उपयोग समुदाय के बने रहने और विकास के लिए अनिवार्य है। तथापि, पारिस्थितिक स्थितियों और समुदाय की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं के बीच सन्तुलन बनाए रखने की जरूरत होती है। नियोजन की प्रक्रियाएँ, पारिस्थितिक व्यवस्थापन और स्थानीय लोगों की सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं के साथ, परिवर्तित होगी।

30.8 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विकास

भारत अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और क्षेत्रों का विकास करने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न कर रहा है। योजनाएं पांच वर्षों की अवधि के लिए बनाई जाती है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारम्भ हुई और इस समय दसवीं पंचवर्षीय योजना चालू है। अब तक जो प्रगति हुई है वो भारत में 55 वर्षों के योजनाबद्ध प्रयत्न का रिकार्ड है जो दस पंचवर्षीय योजनाओं और कुछ वार्षिक योजनाओं के जरिये पूरा किया गया है। विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त परिचय, उनकी स्थानीय क्षेत्र रूपरेखा और विकास पर विशेष जोर नीचे दी गई तालिका के जरिए बताया गया है।

तालिका कं. 30.2
विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्थानीय क्षेत्र विकास

योजना और उसकी अवधि	स्थानीय क्षेत्र की रूपरेखा	विकास पर विशेष बल
1. प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 - 1956	सामुदायिक विकास खण्डों की पहचान की गई	सिंचाई तंत्रों का विकास और कृषि उत्पादन में वृद्धि
2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 - 1961	औद्योगिक सम्पदाएँ स्थापित की गई थी।	औद्योगिक विकास में आत्म–निर्भरता
3. तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 - 1974	गहन कृषि सम्बन्धी जिला कार्यक्रम (IADP)	अर्थव्यवस्था के कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उत्पादन के ज्यादा उच्च स्तरों की प्राप्ति

टिप्पणी

4. चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 - 1974	संतुलित क्षेत्रीय विकास (BRD), आलाकमान समीय विकास कार्यक्रम (CADP)	लक्ष्य क्षेत्र, लक्ष्यसमूह
5. पांचवी पंचवर्षीय योजना 1971 - 1979	विकेन्द्रित नियोजन, जन जातीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, सूखा प्रवृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम।	राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
6. छठी पंचवर्षीय योजना 1980 - 1985	बहु–क्षेत्रीय अभिगम, ड्वाकरा ट्राइसेम, आर.एल.जी.पी. पिछड़े जिले।	गरीबी उन्मूलन, छोटे किसानों का विकास, सीमावर्ती क्षेत्र,
7. सांतवीं पंचवर्षीय योजना 1985 - 1990	कृषि जलवायविक क्षेत्र जलसंभर विकास	स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना
8. आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 - 1997	पंचायतीराज संस्थाएं, एच.ए.डी.पी., बी.ए.डी.पी., डब्लु.जी.डी.पी., एन.इ.सी.	मानव संसाधन विकास, आर्थिक विविधीकरण
9. नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 - 2002	मूलभूत न्यूनतम सेवाएं	मानव संसाधन विकास, लोगों के लिए आवास तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा
10. दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 - 2007	मुख्य नदियों की सफाई, वर्षा जल संभरण (पारम्परिक तरीकों का नवीकरण) नदियों के जल का एक–दूसरे से जोड़ना, सूखे क्षेत्रों में जल पुनःभरण।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख–साधनों की व्यवस्था, सबके के लिए स्वास्थ्य।

पाठगत प्रश्न 30.3

1. क्षेत्रीय नियोजन में स्थानीय लोगों की क्या भूमिका है?

   _____

2. प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष बल किन विकास कार्यों पर दिया गया था?

   _____

3. दसवीं पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य हैं?

   _____

4. स्तम्भ-I में दर्शाई योजनाओं और II में सुझाए स्थानीय क्षेत्र नियोजन को आपस

टिप्पणी

में मिलाइए :

स्तम्भ-I **योजना**		**स्तम्भ-II** **सुझाया गया स्थानीय क्षेत्र नियोजन**
क)	द्वितीय पंच वर्षीय योजना	1) संतुलित क्षेत्रीय विकास
ख)	चौथी पंच वर्षीय योजना	2) औद्योगिक विकास में आत्म निर्भरता के लिए औद्योगिक सम्पदाएँ
ग)	पांचवी पंच वर्षीय योजना	3) निर्धनता उन्मूलन, ड्वाकरा, ट्राइसम, आरएलइजीपी
घ)	छठी पंच वर्षीय योजना	4) मुख्य नदियों की सफाई, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख साधन की व्यवस्था, वर्षा जल संभरण।
ङ)	दसवीं पंच वर्षीय योजना	5) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

30.9 विभिन्न नियोजन क्षेत्रों की अपनी-अपनी आवश्यकताएं

प्रकृति ने सभी क्षेत्रों को कुछ संसाधन प्रदान किए हैं जो क्षेत्र का विकास करने में मदद कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भिन्न–भिन्न समस्याएं और सामर्थ्य शक्तियां हैं। अतः यह नियोजन की बेजोड़ आवश्यकताएं प्रस्तुत करती है। परन्तु प्रत्येक क्षेत्र जिसकी समस्याएं हैं, उसके पास ऐसी समस्याओं को हल करने की संभावनाएँ भी होती हैं। उसी हैसियत से, विशिष्ट क्षेत्रों के विकास और लोगों के कल्याण के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, खानों के क्षेत्रों में खनिज की परतें होती हैं। परन्तु मोटे तौर पर, इन क्षेत्रों को स्वास्थ्य और प्राकृतिक विपदाओं, ध्वनि प्रदूषण, खान की छतों के गिर जाने और जलाक्रान्ति इत्यादि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खनन क्षेत्रों की समस्याओं पर नियोजन के लिए विशेष तौर से विचार किया जा सकता हैं।

शहर में झुग्गी–झोपड़ी बस्ती को सामान्यतः गंदगी, अपर्याप्त आवास तथा मूलभूत सामाजिक सुविधाओं और सुख–साधनों की तीव्र कमी का सामना करना पड़ता है। यहाँ जीवन की गुणवत्ता बहुत खराब होती है और स्वास्थ्य संकटों से भरी होती है। इसलिए स्थानीय क्षेत्र नियोजन में अनिवार्य आधारभूत ढांचे का प्रावधान होना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदूषण की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बाजार क्षेत्र संकुलन, भीड़–भाड़ और, गंदगी से घिरे हैं। फलस्वरूप, औद्योगिक क्षेत्रों के नियोजन में प्रदूषण नियंत्रण की प्राथमिकता होगी, जबकि बाजार क्षेत्रों की प्राथमिकता क्रय–विक्रय के अन्य केन्द्र विकसित करने की होगी ताकि वे दबाव से निर्मुक्त हो सकें और संतुलन व भीड़–भाड़ कम कर सकें। कृषि क्षेत्रों में बाढ़ व सूखे, मृदा अपरदन, प्राकृतिक उर्वरा का कम होते जाना और भूमि–मनुष्य अनुपात के कम होने की समस्याएं हैं, जबकि चारागाही क्षेत्रों में परास भूमि प्रबन्ध, घास भूमियों का खेतों में परिर्वतन इत्यादि की समस्याएं होती हैं। फसलों के प्रारूप में विविधिकरण फसल उत्पादन क्षमता

और बढ़ती हुई कृषि उत्पादकता कृषि नियोजन की प्राथमिकताएं हैं। जबकि पशुचारण क्षेत्रों में नियंत्रित चराई और प्रभावपूर्ण परास भूमि–प्रबन्ध और व्यापारिक पशुचारण की नियोजन प्राथमिकताएं होती है।

विविध भौतिक व सामाजिक–आर्थिक तंत्र वाले क्षेत्रों की अपनी अनूठी आवश्यकताएं होती है। यह आवश्यकता आधारित नियोजन समाधानों की मांग करती है। उदाहरण के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में अतिप्रवण ढलानें, गहन घाटियाँ, मृदा की पतली परत और भूमि की तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर की वहन क्षमता होती है। इसलिए, पहाड़ी क्षेत्रों को अपने विकास के लिए वृक्षारोपण, बागवानी की प्रौन्नति, हर्बल और औषधियुक्त पौधे, पारिस्थितिक पर्यटन और छोटी जलविद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता है। इसी प्रकार से मरुस्थलीय भूमि क्षेत्रों की विशेषता पानी की अत्यधिक कमी के कारण बहुत बड़े क्षेत्र का अनुत्पादक होना, बालू के टीले और ऊसर भूमि होती है। मरुस्थल में विकास के लिए पानी की व्यवस्था नियोजन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहती है। भारत के थार क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर मरुस्थलीय विकास के लिए आवश्यकता आधारित नियोजन का उद्देश्य पूरा करती है।

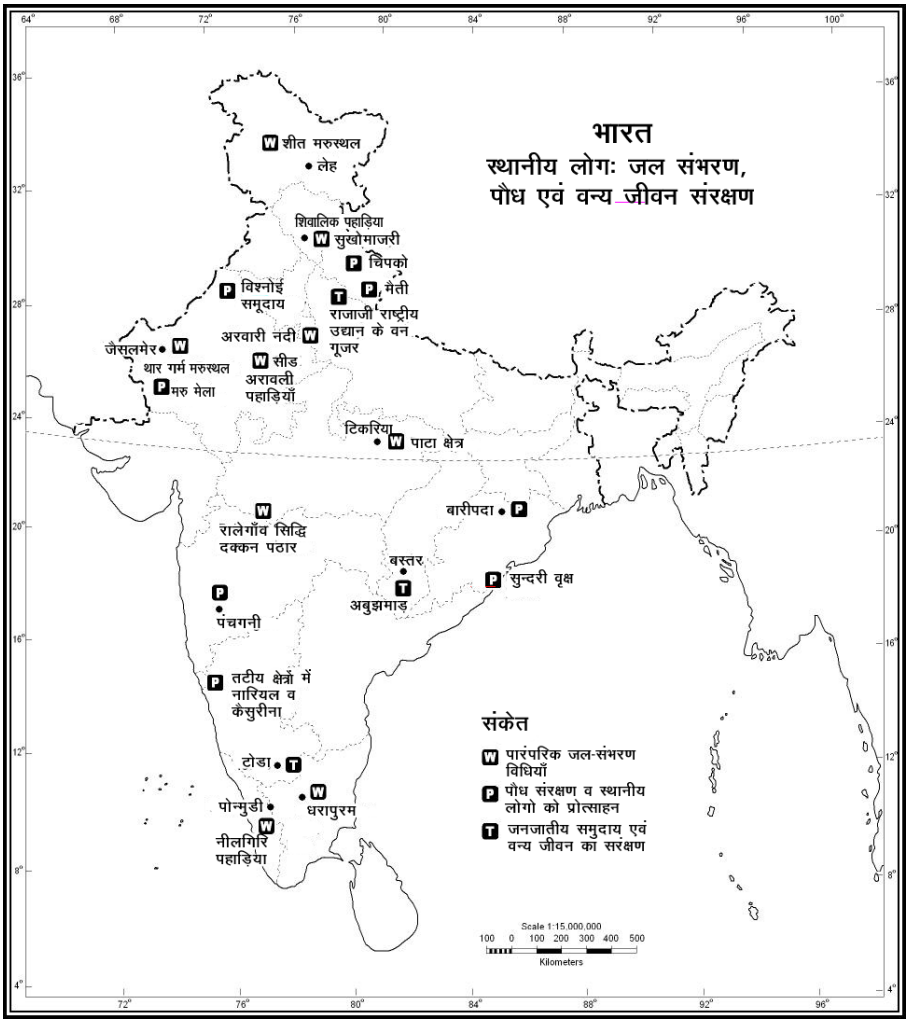

चित्र 30.3: भारत : स्थानीय लोग : जल संभरण, पौधे और वन्य जीवन सुरक्षा

टिप्पणी

आवश्यकता आधारित नियोजन पर संक्षिप्त चर्चा नीचे दी गई है :

(क) जल संग्रहण और प्रबन्ध

ये क्षेत्र जल का वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण उपयोग प्रदर्शित करते हैं, लेह के दूरस्थ ठण्डे रेगिस्तान से थार के गर्म रेगिस्तान तक; मध्य भारत के पाथा क्षेत्र से केरल और तमिलनाडु के दूरस्थ स्थानों तक, जल प्रबन्ध की तकनीकों ने इन क्षेत्रों में जीवन और भू–दृश्य को बिल्कुल बदल दिया है। (राजस्थान में अरवारी और मध्य भारत के पाथा क्षेत्र में टिकरिया के हाल ही के उदाहरण क्षेत्र के जल संसाधनों का संचालन करने के लिए स्थानीय लोगों की पहल है)। भारत के प्रत्येक भाग में, पारम्परिक जल संग्रहण और प्रबन्ध की विधियां भी पाई जाती है।

(ख) वनों की सुरक्षा और प्रौन्नति

इलाके में पारिस्थितिक और जैवीय सन्तुलन बनाए रखने के लिए पौधों और पशुओं की सुरक्षा व प्रौन्नति की जरूरत है। लोग पौधों और पशुओं की सुरक्षा आंशिक रूप से धर्म की वजह से और आंशिक रूप से प्रचलित प्रथाओं और परम्पराओं की वजह से कर रहे हैं। यह समुदाय के दीर्घकालिक हित में प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के उदाहरण हैं।

> पीपल, नीम, तुलसी, बेरी जैसे पौधे हिन्दू परम्परा में पवित्र हैं जबकि खजूर, शाहबलूत, ओक, बरगद इस्लामी, ईसाई और बौद्ध परम्परा में क्रमशः पवित्र समझे जाते हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में पारिस्थितिक स्थितियों के आधार पर, पौधों की सुरक्षा की जाती है। जैसे कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में नारियल और केसुरिना, रेगिस्तानी क्षेत्रों में खजूर और बेरी और पहाड़ी क्षेत्रों में फलोद्यान प्रौन्नति और सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय प्रथाएं हैं। इससे मिलती–जुलती परम्पराएँ पवित्र पशुओं जैसे—गाय, बकरी और भेड़, ऊँट, सांप इत्यादि की सुरक्षा करने की भी है।

(ग) जनजातीय समुदाय और वन्य जीवन की सुरक्षा

जनजातीय समुदाय और वन्य जीव दोनों को वृक्षोन्मूलन के सम्मुख विकास और उत्तरजीविता की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वन निवासियों ने वन्य जीवन की सुरक्षा की है। उदाहरण के लिए राजाजी नेशनल पार्क (उत्तरांखड) के बन गुज्जर लोग, बस्तर के अबुझमाड़ लोग और नीलगिरि के टोडा लोग वन्य जीवन संरक्षण में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। तथापि, इन वन निवासियों में से कुछ को अब बेदखल कर दिया गया है और उनका पुनर्वास उन क्षेत्रों में किया गया है, जहाँ वनों तक इनकी कोई पहुँच नहीं है। ऐसा कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क में और उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में हुआ है। जनजातीय लोगों का जुड़ाव और उनके वन अधिकारों की रक्षा अब वन्य जीवन रक्षा बेहतर तरीकों के उपयोग के कारण हो रही है।

(घ) लोगों को शक्ति : स्थानीय स्तर पर पर्यावरण प्रबन्ध

स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय प्रबन्ध, लोगों को, उनके प्राकृतिक साधनों का प्रबन्ध करने

के लिए ताकत देता है। विकास और कल्याण की गतिविधियों पर बड़ी धन राशि खर्च करने के पश्चात् भी, भारत पर्यावरणीय प्रबन्ध का मुकाबला अच्छी तरह से नहीं कर पाया। अतः, यह महसूस किया गया है कि स्थानीय कार्यकलापों का संचालन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ध्यान रख पाएं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने प्रजातन्त्र में विकेन्द्रित नियोजन सम्भव बना दिया है। स्थानीय स्तर के पर्यावरणीय प्रबन्ध के कुछ उदाहरण मानचित्र क्र. 30.4 में दर्शाया गए हैं।

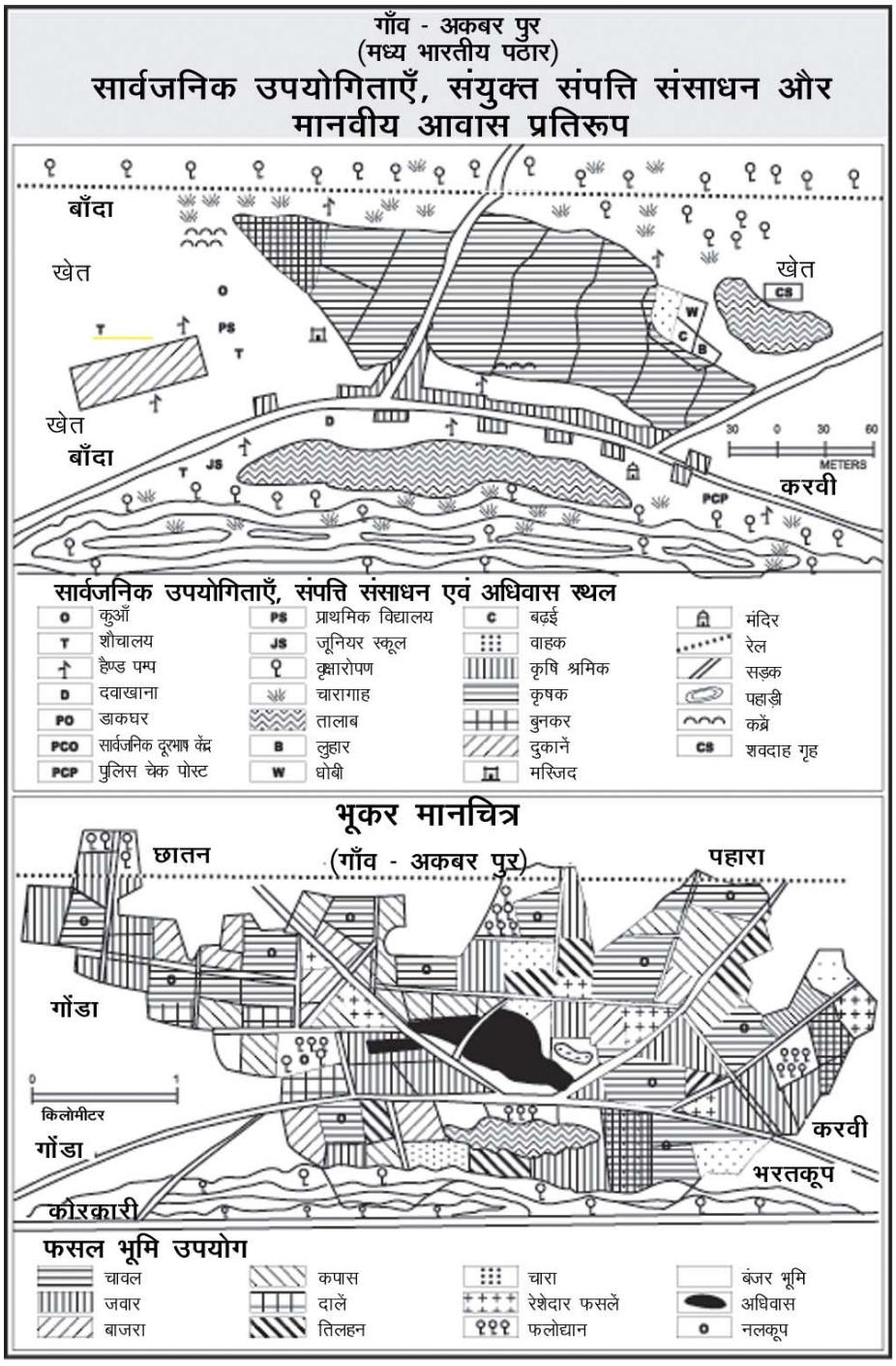

चित्र 30.4 गांव अकबरपुर

टिप्पणी

टैंकों, छोटे बांधों, जल संभरण के लिए छोटे जलाशय, ढलाऊँ पगडंडियों की बगल में बागान और नियंत्रित चारावाही गतिविधियां उन स्थानीय प्रयासों के कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार किया है।

30.10 संसाधन उपयोग और अन्तर्संबंध

वे सब पदार्थ और वस्तुएं जो लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हैं अथवा उपयोग हेतु तैयार हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का उपयोग एक स्थिति है जिसमें प्रकृति प्रदत्त वस्तु उपयोग की जाती है। संसाधनों का सन्तुलित उपयोग होना चाहिए। संसाधनों को संकट सीमा के परे या बिना प्रतिस्थापन के इस्तेमाल करने से पारिस्थितिक तंत्र में और अन्ततः पर्यावरण में असन्तुलन उत्पन्न होता है। अतः संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना अत्यंत आवश्यक है। इससे दीर्घकाल में मानवीय प्रगति में सहायता मिलती है।

(क) संसाधनों के प्रकार एवं उपयोग

संसाधन दो प्रकार के होते हैं : गैर–नवीकरणीय (खनिज सम्पदा) जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद समाप्त हो जाते हैं और विश्व में ऐसे संसाधनों की एक निश्चित मात्रा है; और नवीकरणीय संसाधन (नदियों में ताजा जल, वातावरण में ऑक्सीजन, वन और जैवीय समूह), जो पृथ्वी पर क्रियाशील प्राकृतिक प्रक्रियाओं से मिलते हैं और वार्षिक वृद्धि और, मनुष्य द्वारा उपयोग किए संसाधन समेत, वार्षिक उपभोग के बीच संतुलित हो जाते हैं। आइए देखें किस प्रकार पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और बदले में समाज प्रकृति पर क्या असर डालता है। आज ऐसी जगह मुश्किल से कोई होगी जहां मानव नहीं रह सकता या काम न कर सकता होगा। मानवीय हस्तक्षेप का प्रभाव प्रकृति में बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, खनिज सम्पदा का दोहन करने, ईंधन जलाने, या शुष्क ऊसर भूमि में फसलों की सिंचाई करने के समय, हम प्रकृति से कुछ पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह, औद्योगिक और कृषि अवशेषों और अन्य ऐसे गौण उत्पादों को वायुमंडल और जलमंडल में डालकर, हम पर्यावरण में नए घटक पैदा करते हैं। दलदल भूमि पर खेती करने या परिवारों और औद्योगिक जरूरत के लिए पाइप द्वारा जल की आपूर्ति करने से, हम जल सन्तुलन के कुछ तत्वों को परिवर्तित कर देते हैं। पर्वतों और घाटी के क्षेत्र जैसे दुर्बल पारिस्थितिक तंत्र, वृक्षों को काट गिराने, सड़क निर्माण, चट्टानों को बारुद से उड़ाने और विशाल बांध परियोजनाएं द्वारा जोखिम में पड़ गए हैं। ये गतिविधियां, पृथ्वी की संरचना में परिवर्तन और पारिस्थितिक व्यवस्था में असन्तुलन के लिए जिम्मेदार हैं।

मृदा संसाधनों का फसलों के उत्पादन, व्यापारिक बागान और चारागाहों के लिए उपयोग मनुष्यों द्वारा की जाने वाली पारिस्थितिक अनुकूल गतिविधियां हैं। तथापि, अधिक गहन फसलें लेना या अत्यधिक घास चराई जैसी अवैज्ञानिक परिपाटियों से मृदा अपरदन होने

टिप्पणी

लगता है और यह पारिस्थितिक व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाती है। इसी तरह से, वृक्षोन्मूलन, वनों को काटकर कृषि करने के लिए उन्हें जला देना, उद्योगों का प्रदूषण इत्यादि पारिस्थितिक और साथ ही पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करते हैं। अतः स्थानीय संसाधनों को और पारिस्थितिक अनुकूल तथा वहनीय ढंग से उनके उपयोग को समझना आवश्यक है, जिसके न करने पर पारिस्थितिक संकट अवश्यंभावी हो जाएगा।

(ख) संसाधनों का अवक्षय

लोगों ने अपनी विभिन्न अनुक्रियाओं द्वारा हमारे दोनों, नवीकरणीय और गैर–नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों से काफी कुछ प्राप्त किया है। उनमें से कुछ तो काफी सीमा तक या करीब–करीब पूरे अवक्षयित हो गए हैं और दूसरे बहुत कम सीमा तक अवक्षयित हुए हैं। मानवीय अनुक्रियाएँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि इन्होंने पदार्थों की चक्रीय गति के स्थापित प्रतिमान को पलट दिया है, जिससे पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रक्रियाओं के प्राकृतिक कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं।

संसाधनों का अवक्षय, मानवों का प्रकृति पर बढ़ता प्रभाव और सबसे अधिक, पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ती हुई चिन्ता के विषय हैं। यह चिन्ता ऊर्जा संकट और बढ़ती हुई खाद्य पदार्थों की कमी द्वारा उजागर होती है। परिणामस्वरूप, बहुत गम्भीर पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो सकता है। परन्तु संकट से बचना सम्भव होगा, यदि स्थानीय स्तर से भू–मण्डलीय स्तर तक संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने के उपाय किए जाते हैं और संसाधनों का संरक्षण करने की नीति अपनाई जाती है।

(ग) अनुकूलतम संसाधन उपयोग

समाज द्वारा उत्पादन के दौरान पर्यावरण का रूपान्तरण अवश्यंभावी है। न केवल मानव समाज बल्कि वास्तव में किसी भी रूप में जीवन अपनी गतिविधि द्वारा प्रकृति को प्रभावित करता है। पारिस्थितिक वैज्ञानिक अपने विश्वास में अडिग है कि समाज का विकास मानवों पर अनिवार्य रूप से नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह परिणाम संसाधनों के अवक्षय के पारिस्थितिक और साथ ही आर्थिक संकट को और ज्यादा बढ़ा देता है।

स्थानीय क्षेत्र नियोजन के प्रयत्नों का लक्ष्य उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और वहनीय ढंग से उनके अनुकूलतम उपयोग के बीच सन्तुलन बनाए रखना है, जबकि निजी उद्यम सामाजिक फायदों और हानियों का ख्याल किए बिना लाभ की अभिप्रेरणा द्वारा निर्देशित होते हैं।

यह देखा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र का विकास भी, राजनैतिक या व्यापारिक कारणों द्वारा क्षेत्रों को विकसित करने के प्रति, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। उदाहरण के लिए, ऐशो आराम की वस्तुओं का व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन संसाधनों के समाप्त करने की ओर ले जाता है। इसके परिणामस्वरूप, जन साधारण जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए भी कष्ट उठाते हैं क्योंकि दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यम, व्यवस्था में, अंतर्निहित कमजोरियों का लाभ उठाते हैं, इसलिए संसाधनों के नियोजन और प्रबन्ध में लोगों की सहभागिता अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

टिप्पणी

संसाधनों का उपयोग उनकी उपलब्धता, विद्यमान कार्यकुशलता और समाज की तत्कालीन व भावी जरूरतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। संसाधन नवीकरण की चक्रीय प्रक्रिया को और विकासक्षम विकल्पों की खोज को ध्यान में रखते हुए संरक्षण परिपाटियों की निरन्तर निगरानी करना संसाधन अवक्षय की चुनौतियों का सामना करने के कुछ उपाय हैं।

पाठगत प्रश्न 30.4

1. किस प्रकार स्थानीय आवश्यकताएं प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न–भिन्न होती है?

   _____

2. किस प्रकार स्थानीय संसाधन स्थानीय क्षेत्र नियोजन के लिए महत्वपूर्ण हैं?

   _____

3. संसाधन अवक्षय क्या है?

   _____

4. अनुकूलतम संसाधन उपयोग क्या है?

   _____

30.11 स्थानीय क्षेत्र नियोजन के प्रबंधन में मानचित्रों का उपयोग

स्थानीय क्षेत्र, जहां लोग रहते हैं और काम करते हैं का ज्ञान अति महत्वपूर्ण होता है। क्षेत्र का सूक्ष्म, सही और विस्तृत ज्ञान, योजना के प्रभावपूर्ण ढंग से संचालन में मदद करता है। स्थानीय क्षेत्र योजना तैयार करने के लिए, भूमि की क्षमता, लोगों की कार्य निपुणता और उनके विचारों की रीति को समझना अनिवार्य है। अर्जित जानकारी को, गतिविधियों का निरीक्षण और मार्गदर्शन पर परिचर्चा और अंतर्क्रिया के लिए किसी प्रदर्शनीय ढंग में हस्तांतरित करना चाहिए। प्राथमिक आंकड़ों, मुद्दों और समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से संगठित करना चाहिए जो कि भूमि की विशेषताएं प्रतिबिम्बित करे। इसके लिए मानचित्र, चित्र, चार्ट, फोटोग्राफ और रेखाचित्र बहुत जरुरी है। मानचित्र नियोजकों और भूगोलवेत्ताओं के लिए आशुलिपि का कार्य करते हैं और जनसाधारण का मार्गदर्शन करते हैं।

स्थानीय क्षेत्र उनके भौतिक संगठन और सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के अर्थ में भिन्न होते हैं। सूचनाओं/ज्ञान को एकत्रित व प्रदर्शित करने की विभिन्न तकनीकें हैं। सूचनाओं के प्रस्तुतीकरण के विभिन्न रूपों में से मानचित्र सबसे प्रभावी उपकरण है, जो कि मापक व दिशाओं के उपयोग द्वारा सही व विषय वस्तु केन्द्रित प्रस्तुतीकरण करते हैं। इन सबके अलावा मानचित्र संभालने, समझने व सूचनाओं के संचार में आसान हैं।

टिप्पणी

(क) मानचित्रों, रेखाचित्रों और फोटोग्राफों का उपयोग

मानचित्रों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उनका उपयोग भू–आकृतियों, संसाधनों, मानव बस्तियों, स्थल–विशिष्ट सुविधाओं और सुख–साधनों की पहचान के लिए किया जाता है। मानचित्रों का उपयोग इमारतों के डिजाइन, परिवहन मार्ग और विभिन्न गतिविधियों जैसे बाजार, उद्योग, स्कूल, पार्क, खेल के मैदान इत्यादि के लिए नियोजन दर्शाने के लिए भी किया जाता है। नियोजन परियोजनाओं का औचित्य और व्यवहार्यता भी उसके नक्शों के जरिये आंकी जाती है। बिना पैमाने, दिशा और प्रक्षेपण के चित्रांकन, रेखाचित्र कहलाता है। रेखाचित्र तथ्यों के स्थल विशेष पर प्रस्तुतिकरण के लिए अनगढ़ चित्रांकन के रूप में और लिपिबद्ध प्रलेख को याद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह रेखाचित्र और फोटोग्राफ स्थानीय क्षेत्र नियोजन के अंतिम खाके को अन्तिम रूप देने के लिए काफी उपयोगी है।

(ख) स्थानीय क्षेत्र नियोजन के लिए मानचित्रों का आकार व पैमाना चुनना

मानचित्र बनाते समय कई कारकों को ध्यान में रखना होता है। इन कारकों में मानचित्रों का आकार, दर्शाए जाने वाले विवरण, पैमाने का चुनाव इत्यादि काफी महत्वपूर्ण हैं। मानचित्र का आकार, जिन तत्वों को समाविष्ट करना है, उनके विस्तार को निर्धारित करता है। जो ब्यौरा दर्शाना है वह प्रत्येक तत्व के लिए प्रतीक–प्रयोग और हल्का या गहरा रंग (शेड) निर्धारित करता है। पैमाने का विकल्प, मानचित्र पर क्षेत्र के तथ्य प्रदर्शित करने के लिए उपलब्ध स्थान द्वारा निर्देशित होता है। पैमाना मानचित्र पर दूरी और धरातल की दूरी के बीच अनुपात है। आवश्यकता के अनुसार मानचित्र छोटे या बड़े पैमाने का हो सकता है। छोटे पैमाने का मानचित्र थोड़े ब्यौरे के साथ बड़ा क्षेत्र दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, विश्व मानचित्र, दीवार मानचित्र, एटलस मानचित्र इत्यादि छोटे पैमाने पर रेखांकित किये जाते हैं। इसके दूसरी ओर, बड़े पैमाने के मानचित्र का उपयोग भवन योजना, कृषि सम्बन्धी खेतों/गांव के इलाकों के भूखण्डों के भौगोलिक विवरण सम्बन्धी शीट इत्यादि की योजना प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। स्थानीय क्षेत्र नियोजन, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक वितरण प्रणालियाँ इत्यादि के लिए बड़े पैमाने के मानचित्रों का उपयोग किया जाता है क्योंकि वो छोटे क्षेत्र की बहुत सी जानकारी विस्तार से प्रस्तुत करते हैं।

(ग) स्थानीय क्षेत्र नियोजन के प्रबंधन में मानचित्र

मानचित्र भवन निर्माणकर्ता, विकासकार्य करने वालों, प्रबंधकों और नियोजकों के लिए मूलभूत उपकरण हैं। वो दर्शनार्थियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में और सहभागियों, नियोजकों और लोगों के लिए सफलता के आदर्शों के रूप में कार्य करते हैं। मानचित्र भावी योजनाओं के खाके होते हैं।

टिप्पणी

स्थानीय क्षेत्र का नियोजन करने के लिए आधार मानचित्र अनिवार्य होता है। यह भूमि उपयोग, बाजार, यातायात, उपभोक्ता परिवार इत्यादि से सम्बन्धित सर्वेक्षण करने के लिए सहायता करता है। आधार मानचित्र अन्य विषय विशिष्ट मानचित्र, चित्र और चार्ट बनाने में मदद करते हैं। यह उस इलाके और लोगों का, जिनके लिये नियोजन करना है, मार्गदर्शक होता है।

योजना के मानचित्र का प्रारूप क्षेत्रीय कार्यों के आधार पर बनाया जाता है। आवश्यकता आधारित प्रस्ताव, उनके स्थल, डिजाइन, लागत का ब्यौरा आदि बड़े पैमाने के मानचित्र पर दिखाए जाते हैं। मानचित्र प्रारूप परिचर्चा आयोजित करने और विशेषज्ञों तथा स्थानीय लोगों से सुझाव आमंत्रित करने में मदद करता है। परिचर्चा और सुझाव अन्ततः नियोजन के लिए खाका तैयार करने में मदद करते हैं।

मानचित्र स्थानीय क्षेत्र की मांगों, जैसे कि सार्वजनिक उपयोग की इमारतें जैसे स्कूल, अस्पताल आदि, कोष, सुविधाएं, भिन्न तरह के माप और संभावित व्यय या लागत, जानने के आधार के रूप में काम करते हैं। क्योंकि मानचित्र विस्तृत जानकारी समेटे रहते हैं और स्वः व्याख्याकारी भी होते हैं, अतः वो वित्त प्रदान करने वाली एजेन्सियों की अनुमति के लिए सीधे अपील बन जाते हैं। विषय–विशिष्ट मानचित्र स्थानीय क्षेत्र योजना के प्रस्तुतिकरण, तर्कपूर्ण वाद–विवाद और उसके चरणबद्ध क्रियान्वयन में मदद करते हैं।

मानचित्र बनाने में आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे कम्प्यूटर कार्टोग्राफी, जी.आइ.एस., इमेज प्रौससिंग के उपयोग ने विभिन्न पैमानों पर विभिन्न प्रकार के मानचित्र बनाना सम्भव बना दिया है। इसी तरह, सम्प्रेषण तकनीक जैसे इन्टरनेट, ऑनलाइन, वैबसाइट इत्यादि जानकारी को अन्य लोगों व स्थानों तक हस्तान्तरित करने के लिए संभावनाएँ प्रस्तुत करती हैं। अतः मानचित्रण और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी स्थानीय क्षेत्र नियोजन से सीधे जुड़ी हुई हैं।

30.12 स्थानीय क्षेत्र नियोजन का एक वृत्त अध्ययन : गांव-अकबरपुर (बांदा, उत्तर प्रदेश)

गांव अकबरपुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भौगोलिक रूप से, गांव लगभग 25^0 12' उत्तर अक्षांश और 80^0 47' पूर्व देशान्तर पर स्थित है। गांव मध्य भारतीय पठार की उत्तरी सीमा में स्थित है और बुन्देलखण्ड क्षेत्र का हिस्सा है।

विन्ध्यन पहाड़ियाँ और बदौस वन रेंज गांव की दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी सीमा बनाते हैं। उत्तर की ओर, गांव की, छाटन और पहारा गांवों के साथ संयुक्त सीमा रेखा है। जबकि दक्षिण की ओर इसकी गौण्डा, कुरारी और भरतकूप के साथ संयुक्त सीमा–रेखा है। भूमि की सामान्य ढलान दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर है। संरचनात्मक बनावट के रूप में, विन्ध्यन बलुआ पत्थर ऊपरी सतह बनाता है जिस पर यमुना पार की जलोढ़ मृदा सर्वोच्च परत बनाती है। गांव में सिर्फ तीन प्रकार की मिट्टियां हैं। वन और

टिप्पणी

पहाड़ी मृदा जो पहाड़ की तलहटी के सहारे पाई जाती है और पतली मिट्टी की परत में मिश्रित बजरी के टुकड़े इसकी विशेषता है। काली और पीली मिश्रित मिट्टी आमतौर पर मध्यम अँचल में पाई जाती हैं, जबकि काली जलोढ़ मृदा गांव के उत्तरी भाग में प्रमुखता से पाई जाती है।

अकबरपुर में उत्तर पूर्व की गर्म आर्द्र जलवायु और थार रेगिस्तान की गर्म शुष्क जलवायु के बीच परिवर्ती जलवायु होती है। यहां गर्मियों के दौरान 40^0 - 45^0 से. उच्च तापमान दर्ज किया जाता है, और सर्दियों में 5^0 - 10^0 से. निम्न तापमान दर्ज किया गया है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म के मानसून महीनों में होती है। वार्षिक औसत वर्षा की मात्रा 50 से 80 से.मी. होती है।

गांव में पश्चिम की ओर मस्जिद और दक्षिण पूर्व की ओर मन्दिर है। जबकि गांव की बहुसंख्यक जनसंख्या हिन्दू समुदाय की है, जनसंख्या का लगभग पांचवा भाग मुस्लिम समुदाय का भी है। यह बहु–पेशेवर गांव है जिसमें किसान, चरवाहे, शिल्पी, परिवाहक, व्यापारी और अन्य सेवा प्रदाता है। अतः गांव में लोगों का सुसंगत समूह है।

i) सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था

अकबरपुर मध्यम आकार का गांव है। वर्ष 2005 में इसका क्षेत्रफल 1582 एकड़ और जनसंख्या 3952 थी। गांव में लगभग 382 परिवार हैं। करीब आधे परिवार (197) खेतिहर समुदायों से हैं, इसके बाद खेतिहर मजदूरों के परिवार (106) हैं। अतः लगभग 76.7 प्रतिशत परिवार सीधे कृषि सम्बन्धी गतिविधियों में लगे हुए हैं। करीब 15 प्रतिशत परिवार जुलाहा समुदाय से है और बाकी लगभग 8 प्रतिशत परिवार शिल्पियों और अन्य सेवा प्रदाताओं के वर्ग से हैं। भूमि जोतों के अनुसार 1 प्रतिशत से कम (0.94%) बड़े किसान हैं, करीब 9 प्रतिशत (8.91%) मध्यम किसान और बाकी बहुसंख्यक छोटे और सीमान्त किसान हैं। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के परिवारों की संख्या लगभग 37 प्रतिशत है।

कुल जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत साक्षर है। कुल जनसंख्या का करीब 39.52 प्रतिशत कर्मी (अर्जक) का है जिनमें से 36 प्रतिशत मुख्य कर्मी हैं और लगभग 3 प्रतिशत सीमान्त या अल्पकालिक कर्मी हैं। मुख्य या दीर्घकालिक कर्मी वो हैं जो वर्षभर विशिष्ट कार्य में लगे रहते हैं। जबकि सीमान्त/अल्पकालिक कर्मी वर्ष में कुछ समय में पूरक आधार पर रोजगार में लगे रहते हैं। सामान्य भूमि उपयोग के रूप में, लगभग 113 एकड़ भूमि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। कृषि योग्य ऊसर भूमि और बंजर भूमि 119 एकड़ है। गांव का वन क्षेत्र लगभग 20.54 एकड़ का है जबकि कुल कृषि योग्य भूमि 646 एकड़ है। कृषि के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र 379 एकड़ है, जिसका करीब तीन–चौथाई (287 एकड़) सिंचित बताया गया है।

जहां तक अन्य स्थानों से सम्बन्ध का प्रश्न है, गांव झांसी–इलाहाबाद राजमार्ग और मध्य रेलवे के झांसी-मानिकपुर भाग से अच्छी तरह जुड़ा है। पूर्व की ओर इलाहाबाद का शहर लगभग 135 कि.मी. की दूरी पर स्थित है और करवी नगर लगभग 15 कि.

टिप्पणी

मी. पर है। जबकि पश्चिम की ओर बांदा 55 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। गांव में बस स्टैण्ड है और निकटतम रेलवे स्टेशन $1^{1}/_{2}$ कि.मी. पर है।

ii) कृषि सम्बन्धी भूमि उपयोग

कृषि भूमि उपयोग ऋतु अनुसार बदलता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 63 प्रतिशत खरीफ फसलों के अन्तर्गत है, जबकि करीब 36 प्रतिशत रबी की फसलों के अन्तर्गत आता है। बाकी लगभग 1 प्रतिशत क्षेत्र जैद की फसलों के लिए अलग रखा गया है। खरीफ की फसलों का विवरण यहां प्रस्तुत किया गया है। खरीफ के मौसम में, कुल कृषि क्षेत्र के 32 प्रतिशत भाग पर धान की खेती होती है, ज्वार की करीब 25 प्रतिशत और बाजरे की लगभग 24 प्रतिशत पर खेती होती है। अतः कृषि क्षेत्र का 82 प्रतिशत सिर्फ इन तीन फसलों को अन्तर्गत रहता है। खरीफ की अन्य फसलों में, कपास लगभग 8.00 प्रतिशत, दालें लगभग 4.68 प्रतिशत और तिलहन लगभग 2.78 प्रतिशत पर होती है। फल बागान और रेशे की फसलें 1-1 प्रतिशत पर होती है।

iii) सुख साधन और सामाजिक सुविधाएं

सुख–साधनों और सामाजिक सुविधाओं का वर्णन इलाके के सामाजिक आधारिक ढ़ांचे के स्तर को प्रतिबिम्बित करता है। यह सभी प्रकार के विकास की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। गांव में एक सार्वजनिक फोन आफिस के अलावा पांच व्यक्तिगत फोन हैं। सड़क के किनारे स्थित होने की वजह से, गांव में बस स्टैण्ड है। इसी तरह, भरतकूप निकटतम रेलवे स्टेशन है जो डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है। शैक्षणिक सुविधाओं के सम्बन्ध में, गांव में एक प्राथमिक और एक जूनियर हाई स्कूल है। यहां दो चिकित्सा कर्मी हैं और एक सरकारी दवाखाना है। सड़क के किनारे एक छोटा ग्रामीण बाजार भी विकसित हो गया है। नौ छोटी दुकानें हैं जो मिठाई, नाश्ता, चाय, पान, सामान्य सौदे की वस्तुएं, पत्थर के टुकड़े, ईंधन की लकड़ी, मरम्मत का शैड, चिकित्सा कर्मी इत्यादि से सम्बधित हैं। गांव में सुरक्षा चैक पोस्ट है। पेयजल सुविधा के सम्बन्ध में, गांव में पांच कुएं, 17 निजी पम्प हैं और तीन हैण्ड पम्प सरकार द्वारा लगवाए गए हैं।

iv) संयुक्त सम्पत्ति संसाधन

समुदाय के कल्याण के लिए संयुक्त सम्पत्ति संसाधनों की पहचान और उपयोग इलाके को विकसित करने के महत्वपूर्ण आधार है। अकबरपुर गांव में संयुक्त भूमि, जल, घास और वृक्ष का बड़ा भंडार है जिसे स्थानीय समुदाय के दीर्घकालिक कल्याण के लिए संचालित और बनाए रखने की आवश्यकता है। भूमि संसाधनों के रूप में, विन्ध्यन पहाड़ियों के दक्षिण में पत्थर के टुकड़े और पत्थरों के खण्ड मिलते हैं। काली, पीली और पथरीली मिट्टी सभी प्राथमिक गतिविधियों के आधार के रूप में कार्य करने के अलावा निर्माण सामग्री प्रदान करती है। जल के सम्बन्ध में, गांव में एक बड़ा और एक छोटा तालाब है। बड़ा तालाब जबकि पहाड़ियों के समीप स्थित है, छोटा तालाब उत्तर–पूर्वी दिशा की ओर है। यह तालाब पठारी क्षेत्रों में बहुत आम स्थल होते हैं और

टिप्पणी

पशुओं और वन्य जीवों को जल की आपूर्ति के लिये आधार के रूप में कार्य करते हैं। यह तालाब स्थानीय उपभोग के लिए मछली पालन और जलीय, गिरीदार फल, कमल जैसी फसलें उगाने के लिये भी आधार के रूप में कार्य करते हैं। चारागाह गांव में संयुक्त सम्पत्ति संसाधन है। वो रेलवे और राजमार्ग के साथ–साथ नदियों, झरनों के बगल में और दक्षिण में पहाड़ी रास्ते के साथ भूमि के टुकड़ों के रूप में पाये जाते हैं। गांव के पालतू पशु जैसे भेड़ें, बकरियां, गाय, भैंसे, बैल, टट्टू इत्यादि इन चारागाहों में चरते हैं। वृक्ष एक और महत्वपूर्ण संयुक्त सम्पत्ति संसाधन है। यह वृक्ष मूल्यवान फल, फूल, फर्नीचर की लकड़ी, ईंधन की लकड़ी प्रदान करते हैं और परिवेश को हरा–भरा बनाते हैं। आम और महुआ बड़े वृक्ष हैं और फलों, फूलों, फर्नीचर की लकड़ी के सम्बन्ध में अपने व्यापारिक मूल्य के लिए प्रसिद्ध हैं। यूकेलिप्टस, बबूल, नीम इत्यादि अन्य वृक्ष हैं जो फर्नीचर और ईंधन के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। कदम, कनेर झाड़ियां इत्यादि बौने वृक्ष हैं और भेड़ों व बकरियों द्वारा चरने के लिय उपयोग होते है और पहाड़ी ढ़लानों में फूलदार पौधों के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं।

v) नियोजन प्रस्ताव

उपरोक्त विवरण के आधार पर कुछ नियोजन प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं। इन प्रस्तावों को नियोजन के पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक समूहों में विभाजित किया जा सकता हैं।

(क) पारिस्थितिक नियोजन

पारिस्थितिक नियोजन का लक्ष्य इलाके की सामान्य पर्यावरणीय स्थितियों को सुधारने का है। इसके लिए गांव में भूमि, जल और हरित आवरण को सुधारने के सम्बन्ध में योजना बनाई जा सकती है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए संरक्षण विधियाँ और पहाड़ी ढ़लानों के किनारे की भू–आकृतियों और खेतों में जैविक खाद की संरक्षण परिपाटियों को भूमि की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्रियाशील किया जा सकता है। इसी तरह से, घरेलू, चारागाहों और कृषि के लिए जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल संसाधनों की गुणवत्ता और मात्रा सुधारने के लिए तालाबों को ज्यादा गहरा करने, गाद साफ करने और जल संभरण और बरसाती जल के पुनः संग्रहण के लिए ज्यादा स्थलों की खुदाई करने के लिये उचित योजना बनाई जा सकती है। जल की उपलब्धता खेतों में सिंचाई और जल–भरण का स्तर बढ़ा देगी, जो फिर नए बागानों को जल उपलब्ध कराने के अलावा भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि करेगी।

स्वस्थ व सही पर्यावरणीय व्यवस्था के लिए हरित आवरण के स्तर और जैवसमूह में वृद्धि अनिवार्य है। हरित आवरण में वृद्धि करने के तरीकों में मध्यम और बड़े वृक्षों को राजमार्गों, नदियों, रेलमार्ग के किनारे और तालाबों के किनारों पर और पंचायत की भूमि पर रोपण को समाविष्ट कर सकते हैं। छोटे और बौने वृक्षों को फूल वाले पौधों के साथ पहाड़ी ढ़लान के सहारे रोपा जा सकता है। इस नियोजन प्रस्ताव के

टिप्पणी

लिए वित्तीय और प्रौद्योगिक सहायता वन विभाग, राजस्व जिला नियोजन कार्यालय से उपलब्ध की जा सकती है। एक बार यह नियोजन प्रस्ताव क्रियान्वित हो जाता है तो इन पारिस्थितिक आगत की सुरक्षा और रख–रखाव में स्थानीय लोगों का सहयोग और सहभागिता द्वारा मदद मिलती है।

(ख) सामाजिक नियोजन

पारिस्थितिक और आर्थिक नियोजन के हितों की रक्षा करने के लिए सामाजिक नियोजन आवश्यक है। एक स्वस्थ और सही सामाजिक व्यवस्था संतुलित विकास के लिये परिसम्पत्ति होती है। अकबरपुर गांव में सामाजिक नियोजन के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्त्रियों, बच्चों और वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय है। यहॉ एक छोटा स्वास्थ्य केन्द्र और कम से कम एक प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये अति शीघ्र नियोजन की आवश्यकता है। प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य देखरेख सेवा द्वारा स्वास्थ्य सुधारने और जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रित करने में मदद कर सकती हैं। इसी तरह, गांव की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आंगनबाड़ी और उच्च–प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल होने चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी गांव की अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि कपड़ा बुनाई, बढईगिरी, सुनार का कार्य अभी भी गांव में पारिवारिक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। ग्रामीण युवाओं के उत्प्रवास की समस्या को हल करने के लिए, स्व रोजगार को गांव में जरूर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लोगों की ऋण, बचत और विनियोग की समस्या को हल करने के लिए ग्रामीण बैंक शाखा भी स्थापित की जा सकती है।

(ग) आर्थिक नियोजन

स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए ठोस आर्थिक आधार अनिवार्य है। अकबरपुर गांव में तालाब है जो मछली पालन और जलीय गिरीदार फलों के लिए विकसित किए जा सकते हैं। क्षेत्र में पत्थर के टुकड़ों का अच्छा आधार है। अतः खनन केन्द्र और उत्खनन, आर्थिक गतिविधि के रूप में शुरू किया जा सकता है। इसी तरह से, बालू और मिट्टी निर्माण कार्यो के लिए बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। दुधारू पशु जैसे गाय और भैंसों के लाने से गांव में डेयरी उद्योग सुधारा जा सकता है। इसी तरह, संकर जाति की बकरियां और भेड़े गांव में चरवाहों की आय में वृद्धि कर सकती हैं। इन पशुओं को माँस उद्योग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि यह गांव राजमार्ग के साथ स्थित है, तो यह समीप के नगरों चित्रकूट (करवी) और अटारा के बाजारों में अपने उत्पादों की बिक्री से फायदा उठा सकता है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने के अलावा बैंक और पंचायत घर स्थापित करने से ग्रामीण समुदाय की अपने शहरी प्रतिपक्षों के साथ अंतःक्रिया को आगे और सुधारा जा सकता है। शहर में ग्रामीण उत्पाद नियमित आधार पर बेचे जा सकते हैं।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 30.5

1. मानचित्र बनाते समय किन कारकों का ध्यान रखना होता है?

2. अकबरपुर गांव की भौगोलिक स्थिति क्या है? पाठ में दिए विवरण का उपयोग करते हुए एक रेखाचित्र बनाइए।

3. अकबरपुर गांव का कृषि भूमि उपयोग क्या है?

4. अकबरपुर गांव की नियोजन सम्बन्धी आवश्यकताएँ क्या हैं?

5. अकबरपुर गांव में नियोजन की मुख्य आर्थिक व सामाजिक योजनाओं की चर्चा कीजिए।

आपने क्या सीखा

स्थानीय क्षेत्र नियोजन योजना बनाने की प्रक्रिया है जो स्थानीय स्तर की समस्याओं और मुद्दों के समाधान से सम्बधित है। स्थानीय क्षेत्र की भौतिक और सांस्कृतिक दोनों विशेषतायें होती है, जैसे, क्षेत्र का भू–दृश्य, स्थानीय उत्पाद या लोक नृत्य, हस्तशिल्प आदि। स्थान और लोगों की समस्याएं हल करने के तरीके और साधनों की युक्ति निकालने का प्रयत्न नियोजन है। नियोजन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, छोटे स्थानीय क्षेत्र से लेकर इतने बड़े जितना कि विश्व तक नियोजन किया जाता है। तथापि, यह स्थानीय लोगों के सच्चे प्रयत्न होते हैं जो स्वच्छ, हरित और समृद्धशाली स्थानीय क्षेत्र सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय क्षेत्र नियोजन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, उद्देश्यों का निरूपण करना जो लक्ष्य और प्राथमिकताएं प्राप्त करने हैं उन्हें नियत करना, योजना का निष्पादन करने के लिए स्थानीय और अन्य संसाधनों को जुटाना, योजना के क्रियान्वयन और प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए सामाजिक समूह सृजित करना है। स्थानीय क्षेत्र नियोजन की सफलता मोटे तौर पर इलाके के पारिस्थितिक और सामाजिक–आर्थिक आधार पर निर्भर करती है। इस कारण, स्थानीय क्षेत्र योजनाएं स्थान–स्थान पर काफी भिन्न होती है। स्थानीय क्षेत्र

टिप्पणी

नियोजन के आयाम अनिवार्य रूप से लोगों की मूलभूत और उच्चत्तर आवश्यकताएँ पूरा करने और स्थानीय लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर और आय उत्पन्न करना है। अतः स्थानीय संसाधनों का आवश्यकता–आधारित उपयोग इस नियोजन की पूर्व–शर्त है। स्थानीय संसाधनों का अर्थ भूमि संसाधनों जैसे चट्टानें और मृदा, जल संसाधन, बागान और वन संसाधन से है। स्थानीय संसाधनों का मूल्यांकन आंकड़े इकट्ठे करने, योजना तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में मदद करता है। अतः नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। भारत लोगों के कल्याण के लिए अपनी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रों को विकसित करने के लिए नियोजित प्रयत्न कर रहा है। भारत ने अब तक अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर 10 पंच वर्षीय योजनाएँ बनाई हैं। प्राथमिकताएं भिन्न योजना अवधियों के दौरान बदलती रहीं हैं। तथापि, इन सब योजनाओं ने जबकि लोगों के सामान्य कल्याण का मुख्य उद्देश्य रखते हुए आर्थिक वृद्धि की उच्चतर दरें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। भिन्न क्षेत्रों की अपनी सुव्यक्त समस्याएं और सामर्थ्य होती है और इसलिए वो नियोजन के लिए अपनी–अपनी अलग आवश्यकताएँ प्रस्तुत करते हैं। जल संग्रहण और प्रबंधन, वनों का संरक्षण और प्रौन्नति, जनजातीय कल्याण और वन्य जीवन की सुरक्षा, स्थानीय पर्यावरण का प्रबंधन, स्थानीय पर्यावरण के प्रबंधन के लिए सत्ता लोगों के हाथ में इत्यादि भिन्न क्षेत्रों की उनकी अपनी निराली आवश्यकताओं पर आधारित कुछ नियोजन सम्बन्धी प्राथमिकताएं है। स्थानीय पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग और स्थानीय लोगों की पहल महत्वपूर्ण है। संसाधनों के अवक्षय के प्रकाश में अनुकूलतम संसाधन उपयोग और उनकी नवीकरणीयता की आवश्यकता है। स्थानीय क्षेत्र के विकास और नियोजन के लिए मानचित्र मूलभूत उपकरण हैं। नक्शों, रेखाचित्रों और फोटोग्राफों का इस्तेमाल स्थानीय मुद्दों की पहचान करने में, आंकड़े/जानकारी इकट्ठा करने और स्थानीय क्षेत्र नियोजन के प्रारूप को अन्तिम रूप देने में मदद करता है। क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था, भूमि उपयोग प्रारूप, सुख–साधन तथा सामाजिक सुविधाओं और संयुक्त सम्पत्ति संसाधनों का विश्लेषण करने के लिए वृत्त अध्ययन तैयार करनी चाहिए। वृत्त अध्ययन के परिणामों के आधार पर, नियोजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए। इन प्रस्तावों में क्षेत्र के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक नियोजन के लिए मुद्दों और विशिष्ट योजनाओं का समावेश जरूर करना चाहिए।

पाठान्त प्रश्न

1. स्थानीय क्षेत्र नियोजन के किन्हीं दो आयामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
2. स्थानीय क्षेत्र की योजना तैयार करने की मूलभूत विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
3. किस प्रकार स्थानीय लोग स्थानीय स्व प्रयास द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्र को सुधारने में मदद कर सकते हैं?
4. स्थानीय क्षेत्र नियोजन के प्रबंधन में मानचित्रों की क्या उपयोगिता है?

टिप्पणी

5. जनजातीय क्षेत्रों की अपनी अलग विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

30.1

1. **स्थानीय क्षेत्र** अवस्थिति, स्थल विशिष्ट मुद्दा, वस्तु या समुदाय है। यह दोनों भौतिक और साथ ही सांस्कृतिक भू–दृश्य, स्थानीय उत्पाद प्रस्तुत करता है जैसे, हस्तशिल्प और इलाके की विशिष्टताएं जैसे कि लोक नृत्य, कलात्मक वस्तुएं इत्यादि। स्थानीय क्षेत्र स्थिति और लोगों के साथ शक्तिशाली बन्धन प्रतिबिम्बित करता है।

   नियोजन, लोगों और स्थान को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सुलझाने के तरीके और साधनों की युक्ति निकालने का प्रयत्न है। इसका स्थानीय वातावरण और मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने का भी लक्ष्य होता है।

2. भारत में नियोजन के विभिन्न स्तर हैं:

   स्थानीय क्षेत्र नियोजन, खण्ड या लघु स्तरीय नियोजन, जिला स्तरीय नियोजन, राज्य स्तरीय नियोजन और राष्ट्रीय स्तर का नियोजन।

3. किसी क्षेत्र के नियोजन के लिए तीन चुनौतियां हैं:

   क. पर्यावरणीय गुणवत्ता में कमी

   ख. निर्धनता और कुपोषण

   ग. बेरोजगारी

4. नियोजन से लोगों की मूलभूत अपेक्षाएं–

   क. मूलभूत सेवाओं तथा सुख साधनों की व्यवस्था

   ख. कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए विकासात्मक परियोजनाएं जैसे सिंचाई, उद्योग

   ग. रोजगार उत्पन्न करना और उनके उत्पाद बिक्री करने के लिए बाजार

5. नियोजन की मूलभूल आवश्यकताएं हैं:

   क. उद्देश्यों का निर्धारण

   ख. लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करना

टिप्पणी

ग. संसाधनों को जुटाना

घ. सामाजिक समूह बनाना

ङ. प्रगति का मूल्यांकन और मॉनिटॉरिंग

30.2

1. पारिस्थितिक अनुकूलतम नियोजन के दो उदाहरण हैं:

   क. सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लिये नदियों को नियंत्रित करना।

   ख. बागान

2. संसाधनों की उपलब्धता और मानवीय आवश्यकता के बीच सन्तुलन बनाए रखने की सुव्यक्त जरूरत है क्योंकि नवीकरणीयता और निम्नीकरण के मामले में संसाधनों की सीमाएं होती हैं। अतः मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए।

3. स्थानीय क्षेत्र में वृक्षारोपण निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिये:

   क. भू–आकृति

   ख. जलवायु सम्बंधित स्थितियां

   ग. भू–तत्व सम्बन्धी स्थितियां

   घ. प्राकृतिक वनस्पति

4. मूलभूत और उच्चतर आवश्यकताओं के दो–दो उदाहरण:

   क. मूलभूत आवश्यकताएं (i) सुरक्षित पेय जल

   (ii) मूलभूत शिक्षा और स्वास्थ्य

   ख. उच्चतर आवश्यकताएं (i) तकनीकी शिक्षा

   (ii) उन्नत परिवहन प्रणाली

5. प्रौद्योगिकीय नवीनीकरण और संस्थागत सहायता के दो प्रभाव:

   क. प्रौद्योगिकीय नवीनीकरण (i) कृषि सम्बन्धी विकास

   (ii) सूचना क्रान्ति

   ख. संस्थागत सहायता (i) सबके लिए शिक्षा

   (ii) सार्वजनिक परिवहन प्रणाली

टिप्पणी

30.3

1. स्थानीय लोग विकास की योजनाएँ बनाने के अपने अनुभव, नियोजन योजनाओं के क्रियान्वयन और निष्पादन में और नियोजित परियोजनाओं के रख–रखाव में अपनी सहभागिता के जरिये क्षेत्रीय नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

2. विकास के दौरान निम्न पर विशेष बलः

   क. प्रथम पंचवर्षीय योजना का सिचाई तन्त्रों के विकास पर।

   ख. द्वितीय पंचवर्षीय योजना का औद्योगिक विकास में आत्म–निर्भरता पर।

3. दसवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य मुख्य नदियों की सफाई, बरसात के पानी का संग्रहण, नदियों का आपस में जुड़ाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, साक्षरता अभियान, सबके लिए स्वास्थ्य हैं।

4. कालम I का कालम II से मिलान करें।

   क. 2, ख. 1, ग. 5, घ. 3, ङ. 4

30.4

1. स्थानीय आवश्यकताएं प्रत्येक क्षेत्र में, क्षेत्र–विशिष्ट मुद्दों और समस्याओं और विकास के लिए उपलब्ध संभावित क्षमता के आधार पर भिन्न–भिन्न होती हैं।

2. स्थानीय संसाधन स्थानीय क्षेत्र नियोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि विकास की गतिविधियां अधिकांशतः संसाधनों पर आधारित होती हैं। स्थानीय संसाधनों का उपयोग नियोजन की लागत को कम करता है और स्थानीय लोगों के लाभों को अधिकतम करता है।

3. संसाधन अवक्षय संसाधनों के उपलब्ध भंडार में ह्रास होना है। कुछ संसाधनों का काफी हद तक अवक्षय हो गया है, जबकि दूसरों का अवक्षय कम हुआ है।

4. संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग का अर्थ मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में संसाधनों को सतत् धारणीय बनाए रखने के लिए उनके विवेकपूर्ण उपयोग से है।

30.5

1. मानचित्र बनाते समय कई कारकों को जैसे मानचित्र का आकार, ब्यौरा जो दर्शाना है, पैमाने का विकल्प इत्यादि ध्यान में रखना चाहिए।

2. अकबरपुर गांव की भौगोलिक अवस्थिति $25^{o}12'$ उत्तर अक्षांश पर और $80^{o}47'$ पूर्वी देशान्तर पर है।

टिप्पणी

3. अकबरपुर गांव का कृषि सम्बन्धी भूमि उपयोग प्रमुखतया खरीफ के मौसम में धान, ज्वार और बाजरा और रबी के मौसम में गेहूं, चना, दालें और तिलहन की फसलों का होता है। खरीफ की फसलें करीब 63 प्रतिशत क्षेत्र पर होती है, जबकि रबी की फसलें 36 प्रतिशत क्षेत्र घेरती हैं और बाकी लगभग 1 प्रतिशत जैद फसलों के लिए होता है।

4. अकबरपुर गांव की नियोजन सम्बन्धी आवश्यकताएं मूलभूत सुविधाओं, सिंचाई की सुविधाओं और विकास के लिए कृषि–उद्योगों की व्यवस्था से जुड़ी हैं।

5. अकबरपुर गांव के नियोजन प्रस्ताव पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक नियोजन के शीर्षक के अन्तर्गत देखें।

पाठान्त प्रश्नों के संकेत

1. अनुच्छेद 30.3 देखिए
2. अनुच्छेद 30.5 देखिए
3. अनुच्छेद 30.7 देखिए
4. अनुच्छेद 30.9 देखिए
5. अनुच्छेद 30.7 देखिए